

शुगर टाइम्स



चूपी करता है खाद्यान्न की
20 प्रतिशत आपूर्ति



गन्ना तौल में घटतौली पर
अंकुश लगाने के निर्देश



तहसीलों में बनेंगे बायो
प्यूल और कंप्रेसड गैस



चीनी उद्योग में दुर्घटनाओं को
रोकने के लिए प्रोटोकॉल जरूरी

अतिरिक्त गन्ने को एथेनॉल में
बदलने को प्रोत्साहन

किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में गन्ने का योगदान

टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बढ़ेगी किसानों की आय



SHRIJEE

Shrijee has
supplied
more than
100 FFEs



CLIENTS IN **30** COUNTRIES



- Bannari Amman Sugars Ltd.
- Dhampur Sugar Mills Ltd.
- Shree Renuka Sugars Ltd.
- SNJ Sugars and Products Ltd.
- Bilagi Sugar Mill Ltd.

46 Years of Expertise in Steam Economy

Design & Manufacture of

- Falling Film Evaporator
- Direct Contact Heaters
- Radial Flow Evaporator
- Double Pass Evaporator
- Robert Evaporator
- Steam Transformer
- Condensate Flash Heat Recovery System
- Rapid Boiling Batch Pan
- Split Continuous Pan
- Vertical Crystallizers



Video on
Shrijee's FFE installation
in INDIA

www.shrijee.com | sales@shrijee.com

शुगर टाइम्स

R.N.I.- UPHIN/2018/75505 जनवरी 2023 (वर्ष - 5, अंक - 9)

प्रबन्ध सम्पादक

पी. एस. मिश्रा

सम्पादक

राजेश कुमार चौबे

मुख्य सलाहकार

डॉ. साधू राम शर्मा

(पूर्व गन्ना आयुक्त, म.प्र.)

डॉ. राम मूर्ति सिंह

(पूर्व अपर गन्ना आयुक्त)

डॉ. अजय कुमार साह

(आईआईएसआर, लखनऊ)

ए.एन. सिंह चौहान

(पूर्व एमडी शुगरफेड पंजाब)

वित्तीय सलाहकार

अभिषेक गौर (सीए)

ब्यूरो चीफ

जे.के. रावत (एनसीआर)

एम.एम. अग्निहोत्री (लखनऊ)

फोटोग्राफर

सुरेश वर्मा (लखनऊ)

व्यापार प्रबन्धक

शशि योगेश्वर

अरविन्द दुबे

ग्राफिक्स डिजाइनर

चन्दन भट्टाचार्या

बृजेश कुमार पाण्डेय

सहायक

अजय कुमार



5

प्रदेश की भूमि है सबसे अधिक उपजाऊ



7

गन्ना तौल में घटतौली पर
अंकुश लगाने के निर्देश



27

टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बढ़ेगी किसानों
की आय

कार्यालय

485, भवानी भवन, ममफोर्डगंज,
(शिवाजी पार्क के सामने) प्रयागराज

लखनऊ कार्यालय

567/1, जेल रोड, आनन्द नगर,
लखनऊ

फोन/फैक्स : 0532-2440267,

सम्पर्क : 73554 53462

वेबसाइट : www.sugartimes.co.in

ईमेल - info@sugartimes.co.in,

upsugartimes@gmail.com

मोबाईल

9415305911, 9532882507,
9452935729

नोट - स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, पी.एस. मिश्रा द्वारा क्यूआईएस प्रयागराज से मुद्रित और 485 ममफोर्डगंज (शिवाजी पार्क के सामने), प्रयागराज (यू.पी.) से प्रकाशित। शुगर टाइम्स से सम्बन्धित सभी विवाद केवल प्रयागराज स्थित न्यायालय के अधीन होंगे। शुगर टाइम्स पत्रिका की सदस्यता तथा इसमें विज्ञापन हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान कृपया नगद न करके चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में ही करें। अपरिहार्य कारणों में नगद भुगतान के समय पत्रिका में दिये गये मोबाईल नम्बरों पर सम्पर्क करके ही नगद भुगतान करें। अन्यथा आपकी सदस्यता शुल्क या अन्य प्रकार के भुगतान हेतु शुगर टाइम्स की जिम्मेदारी नहीं होगी - (सम्पादक)

ऊर्जा और देश की समृद्धि में किसानों का है बड़ा योगदान

भारत ने पिछले कुछ सालों से विकसित देश बनने की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ाया है। सरकार द्वारा ऐसी नीतियां लाई गईं जो हमें विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक थीं। विकास के लिए जरूरी क्षेत्र जैसे कि उद्योग स्थापना के लिए सुगम नीति, नीतियों पर अमल करने की दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति तथा अपने उपलब्ध संसाधनों का प्रसार आदि पर जबरदस्त कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी देश की बागडोर संभालने के बाद मजबूती से इन तीनों क्षेत्रों पर अमल किये हैं। विदेशों में देश की धरोहर और अस्मिता का गुणगान जिस तरह से उन्होंने किया था, उसका परिणाम है कि दुनिया भर के चाहे राजनीतिज्ञ हों अथवा उद्योगपति सभी भारत को नये नजरिये से देखना शुरू किये। परिणाम यह है कि दुनिया के बड़े उद्योग भारत में निवेश के लिए आतुर दिख रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करने का हमारा मंतव्य नहीं है परंतु उन्होंने देश के सबसे महत्वपूर्ण और बहुसंख्यक वर्ग किसान के लिए प्रभावशाली नीतियां आरंभ की हैं। जो किसान कभी गरीबी और अभावग्रस्त भारत का प्रतीक बन गया था अब वह इन नीतियों के कारण देश के विकास और समृद्धि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। किसी भी देश की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों में ऊर्जा का स्थान प्रमुख होता है। ऊर्जा की जब बात होती है तो प्रायः हम विद्युत और पेट्रोलियम ऊर्जा की ओर ही देखते हैं। हमारे देश में तकनीकी रूप से सक्षम लोगों की पहले से ही कमी नहीं थी, परंतु ब्रेन-ड्रेन (प्रतिभा-पलायन) के कारण ऐसे हमारे वैज्ञानिक विदेशों में जाकर नये-नये खोज और तकनीकी ईजाद करते रहे हैं। देश में शोध के लिए जब सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं तो परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। देश के वैज्ञानिकों ने विकास के लिए सबसे अहम ऊर्जा के क्षेत्र में नये-नये विकल्प तैयार कर दिये हैं। एथेनॉल से शुरू होकर अब किसानों के उत्पाद अब कई तरह के बायोगैस के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

पारंपरिक खेती की ओर किसानों का लौटना स्वयं उनके लिए तथा पर्यावरण और उपभोक्ता के लिए लाभदायक हो रहा है। जैविक फसल को बढ़ावा देने से जमीन की उर्वरा शक्ति और पर्यावरण को लाभ हो रहा है। जैविक उत्पाद से उपभोक्ता का सेहत अच्छा होता है और किसान को अपनी फसल का अच्छा फायदा मिलता है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य मोटे अनाज जिसमें रसायन और जल की कम जरूरत होती है, को बढ़ावा दे रहे हैं। एपीडा जैसी संस्थायें किसानों के जैविक उत्पाद और मोटे अनाजों को देश के बाहर निर्यात में सहयोग कर रहे हैं। किसान और कृषि क्षेत्र में देश के वैज्ञानिकों ने बड़ी क्रांति ला दी है। आने वाले समय में किसान का फसल पेट्रोलियम पदार्थों के विकल्प, विभिन्न प्रकार के गैसों के उत्पादन और विद्युत निर्माण में प्रमुख भूमिका में होंगे। किसान के उत्पाद जहां विदेशी मोर्चे पर हमारी आयात लागत को घटाने में मदद कर रहे हैं वहीं अपने उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि कर देश को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं।





बलरामपुर चीनी मिल्स लि.,



यूनिट-मनकापुर (गोण्डा)



कृषक भाइयों के बहुमुखी विकास को समर्पित बलरामपुर समूह की इकाई

गन्ना कृषक भाइयों को नव वर्ष की बहुत-बहुत बधाई एवं 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

गन्ना-उपज एवं कृषकों की आय द्रुनी करने हेतु संचालित कार्यक्रम

- नवीन एवं उन्नतिशील गन्ना प्रजातियों का बीज गन्ना उपलब्ध कराना ।
- उत्तम पेड़ी गन्ना उत्पादन हेतु कुशल वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर पेड़ी-प्रबन्धन कार्यक्रम का संचालन ।
- उच्च तकनीकी गुणवत्ता वाले कृषि यंत्र, उर्वरक, कीटनाशक एवं बायो-पोटाश अनुदानित दरों पर सुलभ कराना ।
- खेतों की उर्वराशक्ति बढ़ाने हेतु अनुदान पर प्रेसमड का वितरण ।
- उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त अनुभवी क्षेत्रीय गन्ना सहायक उपलब्ध करा कर कृषकों की आय को दोगुना करने हेतु प्रशिक्षित करना एवं विभिन्न प्रकार के प्रक्षेत्र प्रदर्शन स्थापित कर तकनीकी शिक्षा का प्रसार ।

किसान भाइयों से अपील

- ❑ आप अपनी चीनी मिल को एस.एम.एस. पर्यो पर अंकित गन्ना प्रजाति के अनुसार ताजा एवं स्वच्छ, हंसिये से छिला हुआ गन्ना ही आपूर्ति करें। आपूर्ति किये जा रहे गन्ने में पोढा (जलकल्ला) एवं हरा बंधन बिल्कुल न लायें।
- ❑ लालसड़न रोग के नियंत्रण हेतु फसल चक्र अपनाते हुए बीज एवं भूमि का उपचार अवश्य करें। प्रभावित खेत में एक वर्ष तक गन्ना न लगायें। को0 0238 गन्ना किस्म रोग ग्रस्त हो गयी है, इसके स्थान पर को0 0118 को0 15023 एवं को0लख0 14201 किस्म के गन्ने की बुवाई करें।
- ❑ चीनी मिल द्वारा आपके आस-पास कृषकों के यहां उपरोक्त किस्म के गन्ने की नर्सरी स्थापित कराया गया है, कृषक भाई अपने बीज की व्यवस्था अभी से कर लें। प्रत्येक कृषक अच्छे बीज हेतु एक बीघा उन्नतिशील प्रजातियों के 1/3 ऊपरी हिस्से से बीज नर्सरी स्थापित अवश्य करें।
- ❑ फसल अवशेष जैसे गन्ने की सूखी पत्ती, धान का पुवाल, आदि न जलाकर इस पर ट्रैस मल्वर चलाकर उत्तम कार्बनिक खाद बनायें, इससे आपके खेतों की उर्वरा शक्ति संवृद्ध होगी।

कोविड दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन करें



उमेश सिंह बिसेन
महाप्रबंधक (गन्ना)



मुकेश कुमार जुनजुनवाला
महाप्रबंधक (वाणिज्य)



नीरज बंसल
मुख्य महाप्रबंधक

मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा जैविक खेती से

जैविक खेती को बढ़ावा देने की सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। जैविक खाद की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता न होने के कारण किसान अभी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो किसान जैविक फसल उगा रहे हैं उन्हें उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। जैविक विधि से पैदा हुए अनाज, सब्जी और फलों की भारी मांग को देखते हुए इसके उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकारें कई तरह की सहयोग और सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। वर्तमान में कृषि उपज में बढ़ोत्तरी के लिए बड़े पैमाने पर उर्वरक और पेस्टीसाइड का प्रयोग किया जा रहा है। बढ़ते केमिकल के प्रयोग से उपभोक्ताओं के साथ ही धरती का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए देश में बड़ी संख्या में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। भारत सरकार के सहयोग से करोड़ों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। मृदा परीक्षण के पश्चात खेत में जरूरी खनिज से सम्बन्धित उर्वरक के प्रयोग और जैविक खेती से मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा। - सुधीर वर्मा (सीतापुर)



आर्गेनिक खेती का बढ़े दायरा

जैविक विधि से पैदा किये गये अनाज मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। वर्तमान में जैविक उत्पाद की उपलब्धता बहुत सीमित है जिसके कारण इसके दाम अधिक होते हैं। सभी लोग ऐसे उत्पाद को खरीदने में सक्षम नहीं हैं। परिणाम यह है कि हमारे देश में पैदा होने वाले अधिकतर ऐसे उपज विदेशों में निर्यात किये जाते हैं। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। जैविक खेती करना वर्तमान में थोड़ा कठिन है क्योंकि इसके लिए जरूरी उर्वरक और कीटनाशक की उपलब्धता सीमित है। किसान स्वयं के संसाधनों से इसकी खेती करने में सक्षम नहीं हैं। सामान्य किसान वर्तमान में चल रही खेती के परंपरा में बदलाव का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है लेकिन बहुत ही सीमित दायरे में उसका लाभ किसानों को मिल रहा है।

- संतोष कुशवाहा (प्रतापगढ़)

युवा कैरियर के रूप में अपनायें कृषि

उत्तर प्रदेश सरकार की युवाओं को खेती से जोड़ने की पहल अच्छी शुरुआत है। वर्तमान का युवा चाहे वह गांव का हो या नगर में रहने वाला कृषि क्षेत्र को कैरियर के रूप में नहीं देखता है। कृषि ऐसा क्षेत्र है जो सभी तरह के व्यवसाय को आधार प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी का विकास कर लोगों के जीवन को सहज बनाने का प्रयास है। यही टेक्नोलॉजी जब कृषि क्षेत्र में प्रयोग हुआ तो आज सभी को मनचाही खाद्य पदार्थ मिलने लगा है। भारत सरकार के साथ ही सभी राज्य सरकारों का अधिकतर फोकस गांव और किसान ही होता है। गांव के लोग बड़ी संख्या में पलायन कर नगरों में आ रहे हैं। इससे रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। जागरूक युवा अब कृषि को कैरियर के रूप में अपनाते हुए यदा कदा ही दिखते हैं। प्रदेश सरकार की यह पहल सराहनीय है इससे रोजगार की समस्या दूर हो सकती है। - सुन्दर लाल (फैजाबाद)

ग्लोबल शुगर मार्केट है भारतीय चीनी उद्योग के अनुकूल

दुनिया में इस समय चीनी के दाम देश की घरेलू चीनी मूल्य के समकक्ष है। दुनिया के दो प्रमुख चीनी निर्यातक ब्राजील और थाईलैण्ड में चीनी का उत्पादन अभी नहीं हो रहा है। वैश्विक मांग को पूरा करने का भारतीय चीनी उद्योग के पास अभी तीन-चार महीने का अवसर है। भारतीय चीनी मिलें निर्यात के बड़े समझौते कर रही हैं। दक्षिण भारत और तटीय क्षेत्र की चीनी मिलें निर्यात में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। उत्तर भारत की अधिकतर चीनी मिलें अपने कोटे के चीनी को दक्षिण के राज्यों को स्थानान्तरित कर रही हैं। देश में भी चीनी मिलों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो रहा है। उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश की कुछ चीनी मिलें अभी भी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर पा रही हैं। इस्मा ने चीनी के एमएसपी बढ़ाने की मांग की है। पहले से ही एमएसपी 31 रुपये से अधिक पर चीनी बेची जा रही है। - शैलेन्द्र चौधरी (मेरठ)

चीनी मिलें अब नहीं होंगी बंद

कर्नाटक और तमिलनाडु में बंद चीनी मिलों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार बंद चीनी मिलों में अपनी कई समस्याओं का समाधान देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में सबसे आगे रही है। पिछली सरकारों में बंद चीनी मिलों को चलाने पर सरकार को जनता का भारी समर्थन मिला है। चीनी मिलों से किसानों की आमदनी और बड़ा रोजगार जुड़ा हुआ है। चीनी मिलें अब केवल गन्ने की पेरार्इ कर चीनी ही नहीं बना रही हैं बल्कि पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथेनॉल भी बना रही हैं। मिलों में बनने वाली एथेनॉल के मांग इस कदर बढ़ी है कि उसकी आपूर्ति केवल गन्ने अथवा उसके उपोत्पाद से पूरा नहीं हो पा रहा है। एथेनॉल निर्माण के लिए अब किसानों से अनाज भी खरीदा जा रहा है। एथेनॉल के लिए बढ़ते कच्चे माल की आवश्यकता से किसानों की आमदनी बढ़ रही है। चीनी मिलें अब बहुदेशीय केन्द्र के रूप में सामने आई हैं। - राजेश्वर प्रसाद (बागपत)

आप अपनी पाठकीय प्रतिक्रिया फेसबुक [facebook.com/TheSugarTimes] व्हाट्सअप [7355453462] और ईमेल [upsugartimes@gmail.com] पर भी दे सकते हैं, जिसका प्रकाशन इस स्तंभ में किया जा सकता है। कृपया अपना नाम और पता जरूर दें।

प्रदेश की भूमि है सबसे अधिक उपजाऊ

यूपी करता है खाद्यान्न की 20 प्रतिशत आपूर्ति



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर राजधानी लखनऊ में कृषकों/कृषि उद्यमियों व कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार वितरण किया। इस दौरान सीएम ने महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भूमि सबसे उपजाऊ भूमि है। कृषि में तकनीकी का उपयोग कर किसान अपनी उत्पादन छमता को बढ़ायें।

उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में नई ताकत के रूप में उभर रहा है, चौधरी साहब के अन्नदाता किसानों को समृद्ध बनाने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम शुरू किए जो सार्थक सिद्ध हुए। खेती में लागत कम हो और लाभ ज्यादा हो व उत्पादकता बढ़े इस दिशा में कार्य भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश में किसान फसल बीमा योजना लागू हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में कई कार्य हुए। सरकार में आने के बाद हमने 86 लाख किसानों के कर्ज को माफ किया गया है। आज लागत का डेढ़ गुना एमएसपी कार्यक्रम भी लागू हुआ। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रदेश के 2 करोड़ 60 लाख किसानों को 51 हजार करोड़ की राशि दी जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि गोरखपुर के पिपराइच में नई मिल लगाई गई और नजीबाबाद चीनी मिल का विस्तार किया गया है। हमारी सरकार बहुत मजबूती से किसानों के विकास के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए कृषक उत्पादक संगठन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की कुल आबादी का 16 प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है।

उत्तर प्रदेश की भूमि सबसे उर्वरा भूमि है। देश की कुल खाद्यान्न की 20 प्रतिशत आपूर्ति उत्तर प्रदेश करता है, इसमें और वृद्धि के लिए एफपीओ सहायक हो सकता है। प्रदेश में 75 जनपदों में 89 कृषि विज्ञान केंद्र स्थित हैं। यहां किसानों के लिये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। हमें नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ना होगा, कम सिंचाई में उत्पादकता बढ़ानी होगी। इससे पहले सीएम ने किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर ट्वीट कर हार्दिक शुभकामनाएं दी।

दस किसानों को बांटे गये कृषि यंत्र

शाहजहांपुर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 120वें जन्मदिवस के मौके पर एक दिवसीय किसान सम्मान दिवस मनाया गया। जिसमें डीएम से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी है। कार्यक्रम में तमाम किसानों को बुलाया गया। जिला प्रशासन ने यह आयोजन गन्ना शोध संस्थान में आयोजित किया था। जिसमें पशुपालक, बेसिक शिक्षा, गन्ना उद्यान एवं मत्स्य आदि विभागों ने स्टाल लगाए। जिसमें किसानों को कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पात्र किसानों को कृषि यंत्र भी वितरण किए गए।



कार्यक्रम में जनपद तथा विकासखंड स्तर पर अधिक उत्पादन प्राप्त करने वाले कृषकों को प्रशस्ति पत्र एवं शाल देकर और निर्धारित धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से सम्मानित किया गया। जनपद स्तर पर गेहूँ के उत्पादन में समर सिंह, धान के उत्पादन में बृजबिहारी, सरसों के उत्पादन में रामनाथ, मसूर के उत्पादन में कृष्णपाल, अमरूद के उत्पादन में कमलदीप, केला के उत्पादन में सोनपाल, आलू के उत्पादन में शैलेंद्र सिंह, पातगोभी उत्पादन में नरेन्द्रपाल को प्रथम पुरस्कार मिला। इसके साथ ही दस लाभार्थियों को कृषि यंत्र भी वितरित किये गये।

डीएम उमेश प्रताप सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन की मंशा है कि किसानों की शिकायतों एवं समस्याओं का प्रभावी निस्तारण कराया जाय। उन्हें शासन द्वारा संचालित योजनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाये। उन्होंने किसानों से कहा कि अपनी किसी भी समस्या को उचित स्तर पर सूचित करते हुए निस्तारित करा सकते हैं।

चीनी उद्योग में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रोटोकॉल जरूरी

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) कानपुर द्वारा चीनी उद्योग के लिए 'सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न चीनी उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

शर्करा अभियांत्रिकी के सहायक आचार्य एवं कार्यक्रम के संयोजक संजय चौहान ने अपने सम्बोधन में कुछ चीनी कारखानों में हाल ही में हुये हादसों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये सुरक्षा उपायों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि चीनी और एथेनॉल दोनों ही अत्यंत ज्वलनशील होते हैं अतः इस प्रकार के हादसों से बचने के लिए विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन करना चाहिए। उन्होंने हाल की कुछ घटनाओं की ओर ध्यान दिलाते हुये कहा कि चीनी के पैकिंग क्षेत्र में, जहाँ वातावरण में चीनी के कणों की सघनता अधिक थी और वहाँ पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अनुपालन नहीं किया गया जिससे आग लगने की दुर्घटना हुई।

एनएसआई के निदेशक नरेंद्र मोहन ने अपने सम्बोधन में मानव व मशीनरी दोनों को कोई क्षति न हो इसलिए 'सुरक्षा प्रथम' पर बल दिया। प्रत्येक इकाई को अपना सुरक्षा मूल्यांकन करना चाहिए जिससे खतरे की पहचान कर उससे जुड़े सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। सुरक्षा प्रबंधन के आधारभूत तत्वों में सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान, कर्मचारियों का सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण, और हादसों के दौरान तत्काल लोगों को दुर्घटना क्षेत्र से बाहर निकालने का अभ्यास किया जाना शामिल है एवं इन बातों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के पर्याप्त मूल्यांकन और उन्हें रोकने संबंधी समुचित उपायों से इस प्रकार के हादसों से बचा जा सकता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कानपुर के उपनिदेशक डॉ. अर्काप्रभु साऊ ने अपने व्याख्यान में 'जोखिम बनाम खतरा' इस प्रकरण पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि चीनी कारखानों सहित किसी भी कारखाने में भौतिक, रासायनिक, जैविक, यांत्रिक और मनोवैज्ञानिक जोखिम मौजूद होते हैं और उनसे बचने हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

इस्जेक नोएडा के वरिष्ठ सुरक्षा विशेषज्ञ अमोल सेलोकर ने चीनी कारखानों और एथेनॉल इकाईयों में उनके विभिन्न संयंत्रों के संचालन से जुड़े सावधानियों पर अपनी प्रस्तुति दी।

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड दिल्ली के पूर्णकालिक निदेशक श्री के. शर्मा ने मानव व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित करते हुये बताया कि 96 प्रतिशत दुर्घटनाएँ व चोट असुरक्षित मानव कृत्यों व लापरवाही से होती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास सुरक्षा के नियम, सुरक्षा संबंधी पेशेवर और एक सुरक्षा व्यवस्था होती है जिनका तकनीकी, प्रक्रियागत और व्यावहारिक अनुसरण से हम शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

अग्निशमन एवं अभियांत्रिकी राष्ट्रीय कॉलेज नागपुर के प्राचार्य रमाकांत शर्मा तथा एनएसआई के शर्करा प्रौद्योगिकी के सहायक आचार्य श्री एस के त्रिवेदी ने चीनी कारखानों में दुर्घटना से बचाव के लिए निर्धारित अत्याधुनिक सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के बारे में बताया। ब्रजेश सिंह तकनीकी अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत कर कार्यक्रम का समापन किया।



चीनी उत्पादन के नुकसान को रोकने के लिए प्रयोग करें बीटास्टैब एक्सएल

बीटास्टैब एक्सएल एक नेचुरल एंटी माइक्रोबॉयल है। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी हॉप कंपनी बर्थ-हॉस ग्रुप यूएसए की बीटा टेक एप्लीकेशन की यह प्रोडक्ट है। बालाजी एंजाइम्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग डायरेक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि यह यीस्ट (खमीर) को ग्राम पाजिटव बैक्टीरिया और एसिड बायो प्रोडक्ट से सुरक्षित रखता है, जब गन्ने और चुकन्दर के शुगर का निष्कर्षण किया जाता है। माइक्रोबॉयल शुगर के नुकसान से चीनी के उत्पादन में कमी आती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन के दौरान प्रोसेसिंग की समस्या और बड़े स्तर पर अशुद्धियां जैसे कि लैक्टिक एसिड और डेक्स्ट्रान होता है। हॉप उत्पाद बीटास्टैब एक्सएल चीनी उत्पादन की प्रोसेसिंग में प्राकृतिक रूप से मदद करती है। पिछले दस सालों से वैश्विक स्तर पर यह उत्पाद बैक्टीरिया कंट्रोल में अपनी प्रभावशाली भूमिका को प्रमाणित की है।



आग के हादसे के बाद फिर से शुरू हुई मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल

मेरठ जिले की मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल में फिर से 30 दिसम्बर से पेराई शुरू हो गई है। 26 नवंबर को मिल में आग के हादसे के कारण मिल बंद हुई थी और पेराई सत्र ठप हुआ पड़ा था। किसान गन्ना विभाग और जिला प्रशासन पर मिल जल्द से जल्द शुरू करने के लिए दबाव बना रहे थे। आखिरकार काफी मुशकत के बाद मिल शुरू हुई है, इससे मिल से जुड़े हजारों किसानों को राहत मिली है। मिल द्वारा हर साल लगभग 65 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई होती है। मिल बंद होने के बाद किसानों का गन्ना अन्य मिलों पर डायवर्ट किया गया, लेकिन किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

गन्ना तौल में घटतौली पर अंकुश लगाने के निर्देश

प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने के सख्त निर्देश विभाग को दिये हैं। इन्हीं निर्देशों का पालन करने तथा घटतौली पर नियंत्रण लगाने के दृष्टिगत प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में प्रदेश की समस्त चीनी मिलों के मुख्य वित्त अधिकारी एवं आई टी प्रमुखों के साथ गन्ना आयुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक की गयी।

अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि पेराई सत्र 2022 - 23 गतिमान है तथा कृषकों द्वारा अपने गन्ने की सतत् आपूर्ति चीनी मिलों को की जा रही है। पेराई सत्र 2022-23 में चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रयकेन्द्रों पर गन्ना तौल में घटतौली एवं तौल हेतु प्रयुक्त हो रहे वेब्रिजों एवं साफ्टवेयर में छेड़ छाड़ किये जाने की शिकायतें संज्ञान में आई हैं, जिसके दृष्टिगत प्रदेश की समस्त चीनी मिलों के मुख्य वित्त अधिकारी एवं आई टी प्रमुखों के साथ बैठक कर घटतौली पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश दिये गये।

बैठक के दौरान उन्होंने चीनी मिलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त हो रहे इंडिकेटर के स्थान पर 15 दिवस के अन्दर छेड़-छाड़ रहित इंडिकेटर का प्रयोग कराया जाना सुनिश्चित करें। कांटों में छेड़-छाड़ एवं अवांछित कैलिब्रेशन की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित सेवा प्रदाता एवं तौलन पट्ट विनिर्मिता के साथ-साथ आई टी प्रमुख, मुख्य वित्त अधिकारी तथा सम्बन्धित चीनी मिल के अध्यासी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने कहा कि चीनी मिल गेट पर संचालित गन्ना क्रय केन्द्रों पर तौल लिपिकों की तैनाती ई.आर.पी द्वारा स्थानान्तरण सूची के अनुसार की जायेगी। यदि किसी तौल लिपिक की संलिप्तता घटतौली में पायी जाती है तो उसका लाइसेंस निलम्बित कर निरस्तीकरण कराते हुए चीनी मिल अध्यासी एवं तौल लिपिक दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस बैठक में शिव



जलकुंभी से साफ होगा चीनी मिलों का गंदा पानी

शुगर मिलों का दूषित पानी एक बड़ी समस्या है। इसे साफ करने की तकनीक बेहद महंगी है। इसके साथ ही मिलों में पानी की खपत भी ज्यादा होती है। लेकिन अब इससे निजात पाने के लिए कानपुर में बने देश के इकलौते राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने एक देशी (पर्यावरण मित्र) तकनीक इजाद की है। अब बगैर लागत के चीनी मिलों से निकले दूषित पानी को तालाबों में उगने वाले खर-पतवार जलकुंभी की मदद से दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। प्रयोग में यह मॉडल पूरी तरह से सफल हो गया है।

एनएसआई के निदेशक नरेंद्र मोहन ने बताया कि संस्थान के भौतिक रसायन अनुभाग की ओर से यह तकनीक विकसित की गई है। चीनी मिलों से निकलने वाले



दूषित पानी को प्राइमरी स्टेज पर साफ करने के लिए जलकुंभी (खर-पतवार) का इस्तेमाल किया गया है। शोध में सामने आया है कि जलकुंभी के इस्तेमाल से मल्टीग्रेड फिल्टर एवं पाउडर एक्टिव कार्बन के प्रयोग से साफ किया जा सकता है। प्रयोगशाला में एक के बाद

एक प्रयोग से सामने आया है कि जलकुंभी के प्रयोग से बीओडी, सीओडी, नाइट्रोजन, सस्पेंडेड सॉलिड, कीटनाशकों और हैवी मेटल्स को दूर करने में कारगर साबित हो रहा है। रिसर्च फेलो नीलम चतुर्वेदी ने बताया कि 7 दिनों के ट्रीटमेंट साइकिल से हम दूषित जल से 90 प्रतिशत से अधिक बीओडी और सीओडी कम करने में सक्षम हुए हैं।

भौतिक रसायन के वैज्ञानिक डॉ. सुधांशु मोहन ने बताया कि चीनी मिलों से निकलने वाले गंदे पानी को शोधित करने में काफी खर्चा आता है। संस्थान कम लागत की यूजर-फ्रेंडली तकनीक पर 5 साल से काम कर रहा था। जलकुंभी पर आधारित यह तकनीक केवल कम लागत ही नहीं, ऊर्जा, केमिकल और महंगी शोधन प्रक्रिया से काफी बेहतर है। इस विधि से साफ पानी को मल्टीग्रेड और फिल्टर से और साफ करके इसे सिंचाई के साथ ही मिलों में दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। हम इस तकनीक में रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का समावेश कर प्राप्त पानी को पीने लायक भी बना सकते हैं। इससे मिलों में पानी की खपत और खर्च दोनों ही कम होगा।

सहाय अवस्थी, अपर चीनी आयुक्त, उ.प्र. वी. के शुक्ल, अपर गन्ना आयुक्त विश्वेश कनौजिया, संयुक्त गन्ना आयुक्त विजय बहादुर, सहायक चीनी आयुक्त तथा

मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ चीनी मिलों के आई.टी. हेड एवं मुख्य वित्त अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।



Leader in pumping solution

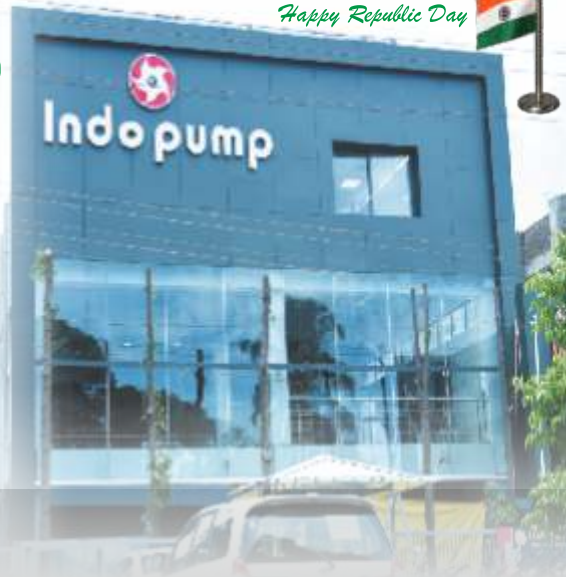
Mfgs. of : Centrifugal Pumps, Hygenic Pumps, Progressive Cavity Pumps, Masecuit Pumps.

Manufacturing Standards :

ISO 2858, ISO 5199, API 610.

www.indopump.com

Happy Republic Day



Pumps & Mechanical Seals
Showroom Concept 1st time in India.



The name in sealing Technology

Indo Seals P. Ltd.

Design and Manufacturers of Mechanical Seals & Rotary Unions

Certified By :



Sales, Service, Spares & Manufacturing.

W-97 A, MIDC, Ambad, Nashik 422 010. Maharashtra (India) Ph.: +91 253 2384705, 2384575

Cell: 9850387332 E-mail : sales@indoseals.com Web : www.indoseals.com

Follow us on



ग्रामीण महिला उद्यमियों की गन्ना विकास में है महती भूमिका

गन्ना विकास विभाग द्वारा प्रदेश के चीनी मिल क्षेत्रों में नवविकसित गन्ना किस्मों के तीव्र संवर्धन सिंगल बड एवं बड चिप विधि द्वारा गन्ना पौध का उत्पादन एवं वितरण से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे किसानों को उन्नत किस्म का गन्ना बीज उपलब्ध होने से कम लागत में उनका उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही नवीन विकसित गन्ना प्रजातियों यथा को.शा. 13235, को. 15023 एवं को.लख. 14201 किस्मों के बीजों का तीव्र संवर्धन होगा।

ऑनलाईन जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों को सम्बोधित करते हुए भूसरेड्डी ने कहा कि गन्ना विकास विभाग ग्रामीण महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी आय बढ़ाने हेतु विभागीय योजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से निरन्तर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि "ग्रामीण महिला शक्ति द्वारा उन्नत गन्ना बीज वितरण कार्यक्रम योजना" सफलता के नये आयाम स्थापित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक प्रदेश के 37 गन्ना उत्पादक जिलों में 3,148 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इन ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा गठित समूहों के माध्यम से अब तक 3,000 लाख सीडलिंग का उत्पादन किया जा चुका है। जिससे उन्हें लगभग ₹.3,792 लाख तथा प्रति समूह औसतन 75,000 से 27 लाख प्रतिवर्ष की आय प्राप्त हुयी है। इस योजना से अब तक 59,525 ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध हुआ है तथा कुल 4,23,680 कार्य दिवस का रोजगार सृजित हुआ है। समूहों द्वारा उत्पादित सीडलिंग की बुआई से कुल 10,592 हे. नवीन गन्ना किस्मों का प्रदर्शन स्थापित कर नवीन किस्मों के गन्ने का आच्छादन बढ़ाया गया।

ग्रामीण महिला उद्यमी पारिवारिक जिम्मेदारियों को सम्भालने के साथ बीज संवर्धन कार्यक्रम योजना में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। इसका फायदा महिला उद्यमियों के साथ-साथ क्षेत्र के किसानों एवं चीनी मिलों को भी मिल रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा यदि बड चिप से गन्ना पौध चीनी मिल चलने से पूर्व तैयार की जाये तो शेष गन्ने से सिरका तैयार कर



महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए 25 दिसम्बर को गन्ना आयुक्त कार्यालय के सभागार में "महिला स्वयं सहायता समूहों से संवाद कार्यक्रम" का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सहारनपुर परिक्षेत्र के महिला समूहों के साथ ऑनलाईन संवाद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा की गयी।



महिलायें अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त गन्ने में बेधक कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु महिला समूहों द्वारा ट्राईकोकार्ड तैयार कराने हेतु उन्हें वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षित भी किया जा रहा है ताकि किसानों को बेधक कीटों से सस्ता एवं टिकाऊ नियंत्रण उपलब्ध हो सके।

संवाद कार्यक्रम में सहारनपुर परिक्षेत्र के 25 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सभी समूहों द्वारा अपर मुख्य सचिव के साथ अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े अनुभव साझा किये गये। समूहों ने अपर मुख्य सचिव को अपनी कार्यशालायें एवं पौधशालाओं को भी दिखाया एवं गन्ना पौध उत्पादन से जुड़े आंकड़े बताये। अपर मुख्य सचिव ने बसन्तकालीन गन्ना बुवाई हेतु अधिक गन्ना पौध उत्पादन हेतु प्रेरित किया। महिला स्वयं सहायता समूहों में से गंगा महिला स्वयं सहायता समूह की संचालिका पूजा चौहान ने बताया कि उनके द्वारा बड चिप से बचे अवशेष गन्ने के माध्यम से 10,000 लीटर सिरके का उत्पादन कर लगभग 7 लाख ₹. की आय अर्जित की गयी है। ट्राईकोकार्ड उत्पादन का प्रशिक्षण भी विभाग द्वारा उन्हें दिया गया है।

कार्यक्रम में प्रबन्ध निदेशक सहकारी चीनी मिल संघ रमाकान्त पाण्डेय द्वारा सुझाव दिया गया कि कोकोपिट के स्थान पर चीनी मिल की बैगास अथवा मिट्टी एवं जैविक खाद आदि का भी प्रयोग कर अपनी लागत को कम कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। अपर गन्ना आयुक्त(विकास) वी.के. शुक्ल द्वारा गन्ना पौध उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले संशोधनों की उपलब्धता एवं अनुदान संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।

डॉ. वी.बी. सिंह, अपर गन्ना आयुक्त (समितियां) ने कहा कि गन्ने के साथ गेहूं की सह-फसल हेतु एफ.आई.आर.बी. विधि में गन्ना पौध का सर्वोत्तम प्रयोग किया जा सकता है तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के कारण देर से गन्ना बोने वाले किसानों को पौध के माध्यम से गन्ना बुवाई करने पर अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन अरुण कुमार, विषय विशेषज्ञ द्वारा किया गया। संवाद कार्यक्रम" के माध्यम से सभी गन्ना बहुल परिक्षेत्रों की ग्रामीण महिला उद्यमियों को विचार साझा करने का मंच प्रदान किया जायेगा।

प्राकृतिक खेती की स्टडी टूर पर जायेंगे युवा गन्ना किसान

वर्तमान में युवा वर्ग खेती से विमुख होकर छोटे-मोटे रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। जबकि खेती को आधुनिक एवं लाभकारी बनाकर वह स्वयं स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। गन्ना विकास विभाग द्वारा युवाओं को गन्ना खेती की नवीनतम तकनीकी सीखने एवं प्राकृतिक खेती की बारीकियां जानने हेतु युवा किसानों के एक अध्ययन दल को कुरुक्षेत्र, हरियाणा भेजा जायेगा। ताकि युवा किसान न केवल कम लागत से अधिक उत्पादन करके खेती को लाभकारी बना सकें वरन प्राकृतिक विधि से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करके मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु महती भूमिका निभा सकें।

गन्ना खेती को उद्यमिता से जोड़ने तथा युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु गन्ना विकास विभाग द्वारा “युवा गन्ना किसान संवाद कार्यक्रम” का आयोजन पाक्षिक रूप से आयोजित कराया जा रहा है। इसी क्रम में मेरठ परिक्षेत्र के 30 वर्ष से कम आयु के युवा पुरुष एवं महिला गन्ना किसानों के साथ अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग संजय आर. भूसरेड्डी की अध्यक्षता में ऑनलाईन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा फार्म मशीनरी बैंक योजना के अन्तर्गत किसानों के लिये उपयोगी महंगे कृषि यंत्रों को नाम मात्र के किराये पर गन्ना किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि यंत्रीकरण को बढ़ावा देकर खेती को आधुनिक एवं लाभकारी बनाया जा सके। उन्होंने युवा किसानों को फार्म मशीनरी बैंक योजना का अधिकाधिक लाभ लेने हेतु प्रेरित किया और कहा कि विभाग द्वारा संचालित राज्य गन्ना प्रतियोगिता एवं उत्कृष्ट कार्य योजना से जुड़कर युवा गन्ना किसान राज्य स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं।

संवाद कार्यक्रम में बुलन्दशहर के बी.टेक कर चुके किसान दीपकान्त शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा पंचामृत योजना एवं प्राकृतिक खेती करते हुए जैविक गन्ने की चटनी तथा गन्ने की आईसक्रीम का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त

संवाद कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव ने मेरठ परिक्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इच्छुक प्रगतिशील गन्ना किसानों का एक अध्ययन दल विभागीय अधिकारियों के साथ प्राकृतिक खेती की बारीकियां सीखने हेतु कुरुक्षेत्र भेजा जाये।



लाभ मिल रहा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे प्रगतिशील किसान एफ.पी.ओ. का गठन कर, ई-नाम के माध्यम से अपने उत्पादों का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अनूपशहर की महिला कृषक खुशी ने गन्ना विभाग की पंचामृत योजना की सराहना करते हुए बताया कि हमारे जैसे बहुत सारे किसान इससे लाभ लेकर अपनी आय को दोगुनी करने का काम कर रहे हैं।

अगौता की महिला कृषक भावना ने बताया कि पांच एकड़ जमीन से गन्ने की सहफसली कर 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष तथा पशुपालन से 30 हजार रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित कर रही हैं।

बुलन्दशहर के किसान जोगेन्द्र सिंह ने गन्ने की खेती में नई किस्मों को अपनाने के संबंध में अपने अनुभव साझा किये वहीं साबितगढ़ की प्रीती जादौन ने गन्ने की खेती के साथ-साथ पशुपालन अपनाने की बात कही।

हापुड़ के अंकित सिंह द्वारा एकीकृत कीट रोग प्रबन्धन पर अपने अनुभव साझा करते हुए फार्म मशीनरी बैंक के अन्तर्गत नये कृषि यंत्रों को जोड़ने का अनुरोध किया। धौलाना हापुड़ के किसान मुनेन्द्र कसाना ने सहफसली खेती के बारे में बताते हुए गन्ने के साथ केले की सहफसली से लाभ लेने के अनुभव साझा किये।

गाजियाबाद के कृषि स्नातक किसान मनीष कुमार ने बताया कि गन्ने के साथ लोबिया की सहफसल लेने से मृदा में नाइट्रोजन स्थरीकरण के चलते यूरिया की मांग कम होती है साथ ही जीवांश की मात्रा में वृद्धि होने से उत्पादन भी बढ़ता है।

बागपत के किसान उपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्राकृतिक खेती करके किसान भूमि और जल का संरक्षण कर सकते हैं। हमारे प्राकृतिक गन्ने से 13.5 प्रतिशत गुड़ की रिकवरी आती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है।

मेरठ के किसान अनमोल खेड़ा ने बताया कि नवीनतम तकनीकी अपनाकर वह 100 एकड़ गन्ने की खेती कर रहे हैं। अनमोल ने किसानों के साथ एफ.पी.ओ. बनाकर लाभ अर्जित करने के अपने अनुभव साझा किये।

युवा संवाद कार्यक्रम के समापन के समय प्रबन्ध निदेशक सहकारी चीनी मिल संघ रमाकान्त पाण्डेय ने युवा किसानों को गन्ना खेती से जुड़े टिप्स प्रदान किये। अपर गन्ना आयुक्त (विकास) वी.के. शुक्ल द्वारा युवा गन्ना किसान कार्यक्रम का समन्वय एवं संचालन किया गया। डॉ. वी.बी. सिंह, अपर गन्ना आयुक्त (समितियां) ने राज्य गन्ना प्रतियोगिता एवं उत्कृष्ट कार्य योजना के माध्यम से राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाने की बात कही।

मेघदूत ऐप से किसान पा सकते हैं मौसम का पूर्वानुमान

दामिनी ऐप इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे द्वारा एवं 'मेघदूत' ऐप भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दामिनी ऐप प्रयोगकर्ता किसान को बचाव के तरीकों के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करता है। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने पर यह उपयोगकर्ता की लोकेशन के अनुसार उस स्थान से 10 किमी के दायरे में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी के बारे में ऑडियो संदेश एवं एस. एम. एस. के माध्यम से अलर्ट करता है, जिससे उपयोगकर्ता समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुँच सकते हैं।

आकाशीय बिजली से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों को गन्ना किसानों तथा विभागीय कार्मिकों के मध्य प्रचारित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इन दिशा-निर्देशों में गन्ना कृषकों को आकाशीय बिजली से बचने के लिए खुले खेतों, पेड़ों के नीचे पहाड़ी इलाकों, चट्टानों का उपयोग न करने की सलाह दी



गयी है। इस एडवाइजरी में गन्ना किसानों तथा विभागीय कार्मिकों को वर्षा ऋतु में बिजली गिरने के समय तालाब, झील तथा बिजली का संचालन करने वाली वस्तुओं से दूर रहने का सुझाव भी दिया गया है तथा यह भी बताया गया है कि आकाशीय बिजली गिरने के समय धातुओं के बर्तन न धोयें तथा स्नान इत्यादि करने से भी बचें।

आकाशीय बिजली के समय आने वाले तूफान के दौरान बिजली के उपकरण या तार वाले फोन का उपयोग न करें एवं बिजली की गरज के दौरान पानी भरे खेत में न रहें तथा बिजली गिरने के दौरान यदि कोई व्यक्ति खुले स्थान पर फंस जाता है और आस-पास कोई छुपने का स्थान न हो तो ऐसी स्थिति में अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखें, नीचे की तरफ थोड़ा

कम अर्थात उकड़ झुकें तथा सुनिश्चित करें कि आपके दोनों पैरों की एड़ी आपस में छू रही हो।

डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा मेघदूत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह एक सरल और उपयोग में आसान मोबाइल एप्लिकेशन है जो मौसम की जानकारी के आधार पर किसानों को फसल जोखिम प्रबन्धन से संबंधित सलाह प्रदान करता है। यह ऐप भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की एक संयुक्त पहल है।

एप हर मंगलवार और शुक्रवार को एग्रो मेट फील्ड यूनिट्स (ए.एम. एफ.यू.) द्वारा जारी फसल पर जिलेवार सलाह और पूर्वानुमानित मौसम की जानकारी प्रदान करता है। यह किसानों को मौसम के अनुसार निर्णय लेने तथा फसलों की बुवाई कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई के समय का निर्धारण आदि में भी सहायता प्रदान करता है।



बलरामपुर चीनी मिल्स लि०, बलरामपुर

(सल्फर रहित उच्च कोटि के चीनी निर्माता)



की ओर से क्षेत्रवासियों, गन्ना कृषकों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को बलरामपुर प्रबंधतंत्र की ओर से

“गणतंत्र दिवस”

के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं

किसान भाइयों से विनम्र निवेदन

- चीनी मिल्स को साफ व ताजा गन्ना की आपूर्ति करें।
- कृषक भाई अपना-अपना बीज स्वयं रोक कर रखें जिससे बुवाई के समय बीज की परेशानी न हो।

गन्ना प्रजाति को० 0238 लाल सड़न रोग से प्रसिद्ध हो गयी है अतः इसके स्थान पर बसन्तकालीन गन्ना बुवाई में को० 0118 , 15023 एवं को० लख 14201 प्रजाति की डी बुवाई करें।



(निष्काम गुप्ता)
मुख्य महाप्रबंधक
बलरामपुर चीनी मिल्स लि०,
इकाई - बलरामपुर

अधिक उपज हैं हमारी शान।
कम लागत और खुशी किसान।।

गन्ना विभाग तैयार कर रहा है कुशल मानव संसाधन

भारत सरकार द्वारा कार्यालयों एवं औद्योगिक इकाईयों की मांग के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करने हेतु गन्ना विकास विभाग कार्यक्रम का अनुपालन कर रहा है। भारत सरकार की नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (एनएटीएस) के माध्यम से ग्रेजुएट/डिप्लोमा इंजीनियर अप्रेंटिसशिप हेतु विभाग द्वारा एनएटीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आदि प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों को ग्रेजुएट/डिप्लोमा इंजीनियर उपलब्ध होने प्रारम्भ हो गये हैं।



इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि इस योजना के अर्न्तगत अभ्यर्थी को मासिक स्टाइपेन्ड ग्रेजुएट इंजीनियर को रु. 9000 तथा डिप्लोमा इंजीनियर को रु. 8000 दिये जाने का प्राविधान है, जिसमें 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा चीनी मिलों को की जाएगी।

अप्रेंटिस के लिए portal.mhrdnats.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। सहकारी चीनी मिलों में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (एनएपीएस) के अर्न्तगत 722 आई.टी.आई. उतीर्ण छात्र तथा आई.टी.आई./डिप्लोमा/बी.टेक. के अध्ययनरत् 554 छात्र लाभान्वित हुये हैं। उन्होंने बताया कि इंटरशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु ऐसे जो प्रोफेशनल कोर्स/स्नातक/परास्नातक/अनुसंधानरत विद्यार्थी हैं और जिसके द्वारा पिछले सेमेस्टर में कम से कम 55 प्रतिशत अंक हैं के लिये इंटरशिप कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

कार्यक्रम में कृषि, विपणन, लेखा, विधि, कम्प्यूटर, शर्करा तकनीकी, अभियन्त्रण, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, सांख्यिकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण आदि के विद्यार्थी वेबसाइट www.upcane.gov.in पर जाकर इंटरशिप टैब पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण उनको भविष्य में रोजगार प्राप्त किये जाने की दशा में व्यवहारिक रूप से कुशल, अनुभवी व कार्यदक्ष बनाने में सहायक होगा।

इंटरशिप की अवधि तीन चरणों में होगी जो 21, 30, 60 एवं 120 दिनों में पूर्ण की जाएगी। प्रशिक्षणकाल में प्रशिक्षु की कम से कम 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इंटरशिप कार्यक्रम के सम्पन्न होने के उपरान्त प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा अपने संपूर्ण किये गये कार्य के संबंध में स्वमूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके पश्चात ही सफल प्रशिक्षुओं को संबन्धित संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा। अब तक गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न विषयों से संबंधित लगभग 450 इंटरनस को प्रशिक्षण के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। इंटरशिप/अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हेतु प्रशिक्षु का चयन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता एवं अर्हताओं के आधार पर किया जाएगा।

किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को दें प्राथमिकता

त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान हेतु गन्ना विकास विभाग ने सख्त रूख अपना लिया है। समस्त चीनी मिलों को 15 जनवरी, 2023 तक गन्ना मूल्य भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में प्रदेश की समस्त निजी सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिल समूहों के ग्रुप हेड तथा एकल इकाईयों के महाप्रबन्धक/यूनिट हेड्स एवं वित्त नियंत्रकों के साथ चीनी मिलवार गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में गन्ना मंत्री द्वारा चीनी मिलों को पेराई सत्र 2021-22 के अवशेष गन्ना मूल्य का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये। गन्ना मंत्री ने चीनी मिल प्रतिनिधियों को आदेशित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार चीनी मिलों को समय से भुगतान करने के लिए समस्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रही है, ऐसी स्थिति में चीनी मिलों को भी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर गन्ना मूल्य भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें टैंगिंग आदेश का अक्षरशः अनुपालन करें कोई भी मिल चीनी के विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि का व्यावर्तन करती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पेराई सत्र 2021-22 के कुल देय गन्ना मूल्य का लगभग 75 प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान अब तक किया जा चुका है तथा अवशेष भुगतान चीनी मिलों को त्वरित गति से करना होगा, गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान नहीं करने पर उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज होगी और वसूली प्रमाण पत्र भी निर्गत की जायेगी। इसके अतिरिक्त भुगतान में लापरवाह चीनी मिलों को आवंटित गन्ने में भी कटौती की जाएगी। गन्ना मंत्री श्री चौधरी ने चीनी मिलों एवं विभागीय अधिकारियों को पेराई सत्र के दौरान घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा गन्ने की कालाबाजारी करने वाले अराजक तत्वों पर सख्त कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है।

समीक्षा बैठक में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग संजय आर. भूसरेड्डी ने कहा कि चीनी मिलें एवं गन्ना किसान एक दूसरे के पूरक हैं। गन्ना किसान एवं उनका परिवार अपने आर्थिक जरूरतों के लिए चीनी मिलों पर आश्रित हैं, इसलिए चीनी मिलों को सदैव गन्ना मूल्य भुगतान एवं अन्य व्यवस्थाओं के सुधार हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी, 2023 तक गन्ना मूल्य भुगतान न किये जाने पर चीनी मिलों पर एफ.आई.आर. करायी जायेगी। गन्ना मूल्य भुगतान पर केंद्रित समीक्षा बैठक में गन्ना विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सभी चीनी मिलों के मुख्य वित्त अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में गन्ने का योगदान

गन्ना फसल एक ऐसी महत्वपूर्ण नगदी फसल है जो ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाले समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराने और किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। आज के समय में गन्ना उत्पादक किसानों के लिए यह फसल आजीविका एवं आर्थिक समृद्धि का मुख्य साधन बन चुकी है। गन्ना बुवाई की वैज्ञानिक विधियों एवं नयी गन्ना किस्मों ने गन्ना उत्पादन और उत्पादकता के साथ-साथ किसानों की आमदनी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। परिणामस्वरूप भारत देश आज चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ विदेशों में निर्यात करने में भी सक्षम हो गया है।

■ अजय कुमार साह एवं हिमांशु पाण्डेय आईआईएसआर, लखनऊ

वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार सम्पूर्ण देश में लगभग 54.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल पर गन्ना बुवाई की गई और जिससे गन्ना उत्पादन लगभग 4316.12 लाख टन प्राप्त हुआ तथा औसत गन्ना उपज लगभग 82 टन प्रति हैक्टेयर रहा। वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 27.60 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल पर गन्ना बुवाई की गई और उत्पादन लगभग 2272.19 लाख टन रहा तथा औसत उपज लगभग 82.31 टन प्रति हैक्टेयर है।

किसानों के आर्थिक विकास में गन्ना फसल का योगदान:-

बदल रहे तकनीकी परिवेश में दुनिया आगे बढ़ने की होड़ में है, वहीं हमारे गन्ना उत्पादक किसान भाई भी कहीं पीछे नहीं हैं। देश में लगभग 600 लाख किसान और 5 लाख कुशल श्रामिक गन्ना फसल से सीधे जुड़े हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार भारतीय चीनी उद्योग प्रति वर्ष लगभग 1.0 लाख करोड़ का कारोबार गन्ना फसल से करता है। गन्ना उत्पादक किसानों के आर्थिक विकास में गन्ना संस्थान एवं चीनी मिलों का अतुलनीय योगदान रहा है जिसके परिणामस्वरूप किसानों ने गन्ना फसल पर अधिक जोर दिया है और गन्ना बुवाई की वैज्ञानिक

विधियों को अपनाकर गन्ना फसल के साथ अन्तःफसली खेती करना भी प्रारम्भ किया है। जिससे उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ने में भी सफलता हासिल हुई है।

किसानों के सामाजिक विकास में गन्ना फसल का योगदान:-

भारत देश में बड़े पैमाने पर गन्ना फसल को उगाया जाता है जो ग्रामीण समुदाय के लिए रोजगार एवं आय मुहैया कराने का अच्छा स्रोत है। गन्ना फसल की खेती करने पर लगभग पूरे वर्ष श्रमिकों की आवश्यकता होने के कारण ग्रामीण समुदाय के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं उत्पन्न होती हैं

जिससे भारी संख्या में ग्रामीण परिवारों को मजदूरी करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और गन्ना उत्पादक किसानों को एक मुक्त आय प्राप्त होने से पूँजी का समुचित उपयोग करके अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों का निर्वाहन आसानी से कर पाते हैं। आज गन्ना उत्पादन की वैज्ञानिक खेती ने एक नया रूप ले लिया है जो किसानों के सामाजिक विकास में वरदान साबित हो रही है। अधिकतर किसान परम्परागत खेती को छोड़कर वैज्ञानिक विधि से गन्ना उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिये हैं। जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वैज्ञानिक बुवाई विधियों और नयी गन्ना किस्मों ने उत्पादन में एक प्रकार से क्रांति ला दी है उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश की औसत उत्पादकता 40 टन प्रति हैक्टेयर (1950-51) से बढ़कर 82 टन प्रति हैक्टेयर (2021-2022) से भी अधिक हो गई है जिसका प्रमुख श्रेय हमारे देश के गन्ना उत्पादक किसानों एवं वैज्ञानिकों को जाता है। इनके अथक प्रयास और परिश्रम से



उत्तर प्रदेश में विगत पाँच वर्षों में गन्ना उत्पादन की रूप रेखा का विवरण

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	विगत 5 वर्षों में वृद्धि दर (%)
गन्ना क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर)	22.99	27.94	26.79	27.40	27.60	20.05
गन्ना उत्पादन (लाख टन)	1820.75	2249.20	2172.53	2232.82	2272.19	24.79
गन्ना औसत उपज (टन/हैक्टेयर)	79.19	80.50	81.10	81.50	82.31	3.93
चीनी उत्पादन (लाख टन)	120.50	118.22	126.37	110.59	101.98	-15.50

स्रोत:- उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास 2022

हमारा देश चीनी निर्यात करने में सक्षम हो गया है। सितम्बर 2022 को समाप्त हुए पेराई सत्र में भारत ने लगभग 110 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया है।

गन्ना उत्पादन में आने वाली समस्याएँ:-

किसानों को गन्ना फसल उत्पादन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो निम्नवत है।

गन्ना किस्म का चयन:-

गन्ना उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में सबसे अहम योगदान गन्ना किस्म का होता है। जानकारी के अभाव में किसान गन्ना किस्म का बेहतर चयन नहीं कर पाते हैं तथा पुरानी रोग एवं कीट ग्रसित गन्ना किस्मों के बीज की बुवाई करते हैं जिससे उचित उत्पादन प्राप्त न होने के कारण गन्ना उत्पादक किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है।

नवीन गन्ना बुवाई विधियों की जानकारी का अभाव:-

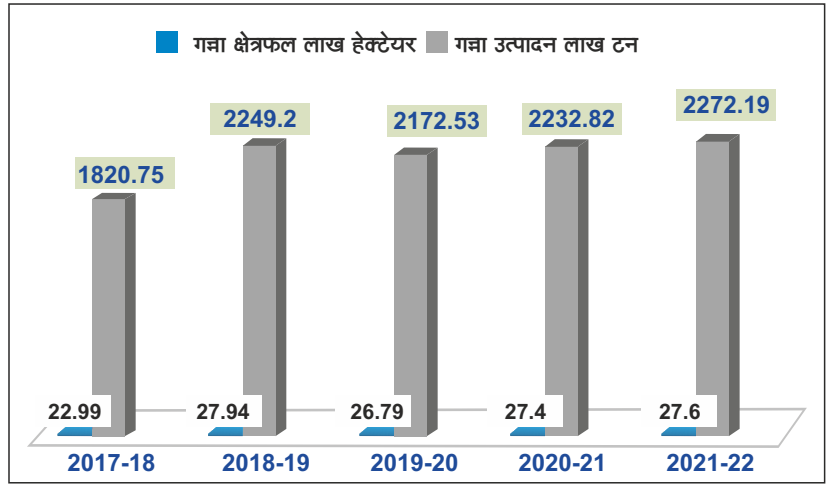
नवीन गन्ना बुवाई विधियों को जानना गन्ना उत्पादक किसानों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। परंतु अभी भी बहुत से गन्ना उत्पादक किसान नवीनतम बुवाई विधियों के अभाव में परंपरागत तरीके से खेती करते हैं जिससे बीज की मात्रा का अधिक प्रयोग करने के कारण उत्पादन लागत अधिक आती है।

खाद एवं उर्वरक की जानकारी का अभाव:-

वैज्ञानिकों के द्वारा संस्तुत की गई खाद एवं उर्वरकों की मात्रा का प्रयोग न करके किसानों द्वारा खाद एवं उर्वरकों के अंधा-धुंध प्रयोग से कीट एवं रोगव्याधियों का प्रकोप और अधिक बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप गन्ना उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। साथ ही महत्वपूर्ण प्रकृतिक संसाधन (मिट्टी तथा भूमिगत जल) की गुणवत्ता में भी हास हो रहा है।

सिंचाई जल की बर्बादी:-

अधिकतर गन्ना उत्पादक किसानों को सिंचाई जल बचत तकनीक की जानकारी न होने के कारण किसान अभी भी फ्लड सिंचाई विधि से खेत में पानी देते हैं। जिसमें लगभग 30-40 प्रतिशत पानी ही फसल के उपयोग में आ पता है। अतः किसानों को गन्ना सिंचाई के लिए स्किप फरो विधि या ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाना अत्यंत आवश्यक है।



उन्नत गन्ना उत्पादन के लिए सुझाव

गन्ना बुवाई के समय गन्ना उत्पादक किसानों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है।

- ❖ नवीनतम गन्ना किस्मों की खेती करना एवं नई गन्ना किस्मों का बीज उत्पादन करना।
- ❖ गन्ना बुवाई से पहले रोग एवं कीट रहित गन्ना किस्मों का चयन करना और गन्ना बीज को कीट एवं रोगव्याधियों से बचाने के लिए कीटनाशक/कवकनाशक से उपचारित करना अत्यन्त आवश्यक है।
- ❖ गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए सही समय पर सिंचाई और खाद एवं उर्वरकों का प्रबंधन करना।
- ❖ गन्ना फसल में लगने वाले खरपतवार एवं रोगव्याधियों की देख रेख करना और समय-समय पर दवाई इत्यादि से खरपतवार एवं रोग नियंत्रण करना अत्यन्त आवश्यक है।
- ❖ गन्ना बुवाई के उपरांत पौध एवं पेड़ी प्रबंधन पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
- ❖ परिपक्व गन्ना की कटाई समय पर करके अतिशीघ्र पेराई के लिए भेजना।
- ❖ उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर गन्ना खेती की जाए तो किसान न सिर्फ और अधिक समृद्ध एवं खुशहाल होंगे बल्कि चीनी उद्योग को और अधिक सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे।

किसानों की समस्याओं का कराया जायेगा निराकरण

गन्ना फसल में सबसे अधिक नुकसान चोटी बेधक कीट द्वारा हो रहा है। इसके लिए चीनी मिल स्तर पर किसानों की पूरी मदद की जायेगी। धामपुर बायो आर्गेनिक्स लि.

के प्रबन्ध निदेशक गौतम गोयल ने क्षेत्र के किसानों के साथ सीधे संवाद स्थापित करने के लिए उनके साथ बैठक की थी। उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ने की फसल से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए चीनी मिल सभी तरह का सहयोग करेगी। किसानों ने इस दौरान उनसे मांग



किया कि चीनी मिल सही कीटनाशक खरीदकर कृषकों को स्वयं उपलब्ध कराये। किसान कई बार ऐसे कीटनाशक का प्रयोग करते हैं जो प्रभावशाली नहीं होता है। केन फंक्सनल के हेड राजीव शर्मा ने चीनी मिल द्वारा मृदा परीक्षण, भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने तथा मृदा संरचना में सुधार की योजनाओं पर जानकारी दी। सीईओ संदीप शर्मा ने को 0238 किस्म पर अपने विचार साझा किये। बैठक का संचालन मुख्य महाप्रबंधक (गन्ना) आजाद सिंह ने किया। इस अवसर पर ईडी कुंवर विजय कुमार गोयल, युनिट हेड संजय शर्मा, मुकुल शर्मा, पंकज अग्रवाल, नरेन्द्र गुप्ता तथा कुलदीप शर्मा आदि के साथ क्षेत्र से आये प्रगतिशील किसान शामिल हुए थे।

डालमिया जवाहरपुर में ग्रेन से शुरू हुआ एथेनॉल उत्पादन



उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आबकारी, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय आर. भूसरेड्डी ने जनपद सीतापुर में नवस्थापित डालमिया भारत शुगर एण्ड इंडस्ट्री लिमिटेड की जवाहरपुर युनिट में ग्रेन बेस आसवनी का 3 दिसम्बर को उद्घाटन किया। यह आसवनी पूर्णतया अनाज पर आधारित है, जिसके संचालित होने से कृषकों और स्थानीय लोगों को भारी लाभ होगा। भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) में आसवनी में बनने वाले एथेनॉल की आपूर्ति की जायेगी। इस अवसर पर भूसरेड्डी ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य प्राप्त होगा। किसानों का अनाज यदि खराब भी हो जाता है तो उसे भी डिस्टिलरी खरीदेगी।

अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि राज्य में 121 चीनी मिलें हैं जिनमें से अधिकतर मिलों में हम लोगों ने डिस्टिलरी प्लांट स्थापित कराये हैं। प्रदेश में पहले 58 डिस्टिलरियां थी अब बढ़कर 98 हो गई हैं। डिस्टिलरियों में पोटोबुल और नॉल पोटोबुल अल्कोहल

उत्तम शुगर मिल्स बढ़ाएगी डिस्टिलरी और गन्ना पेराई क्षमता

उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने बरकतपुर प्लांट में डिस्टिलरी क्षमता (एथेनॉल) को 150 केएलपीडी से बढ़ाकर 250 केएलपीडी करने की मंजूरी दे दी है। परियोजना की लागत 56 करोड़ रुपये होगी, और इसके लिए भारत सरकार की खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ब्याज अनुदान योजना के तहत आंतरिक स्रोतों और ऋणों के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बोर्ड ने मिल की केन क्रशिंग क्षमता को 23750 टीसीडी से बढ़ाकर 26200 टीसीडी करने को भी मंजूरी दी। परियोजना के लिए आंतरिक संसाधनों/ऋणों के माध्यम से 40 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जाएगा।

का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता 24 करोड़ बल्क लीटर से बढ़कर 200 करोड़ बल्क लीटर वार्षिक हो गयी है। जिससे हमारी फॉसिल फ्यूल एवं ग्रीन फ्यूल निर्भरता कम हो रही है, जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा में गुणात्मक बचत हो रही है। ग्रुप के एईडी सुधीर वर्मा ने बताया कि डिस्टिलरी में प्रतिदिन 110 किलो लीटर का उत्पादन होगा। वर्ष में कुल 385 लाख लीटर अल्कोहल बनाया जायेगा। उद्घाटन के अवसर पर उप गन्ना आयुक्त एस.बी सिंह, जिला गन्ना अधिकारी संजय सिसोदिया और चीनी मिल के हेड ए.ए.बेग, यूनिट हेड कुलदीप कुमार, सतीश मलिक तथा अजय मान आदि के साथ ही गन्ना एवं चीनी विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।



डालमिया भारत शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०

(शुगर एवं डिस्टिलरी यूनिट - निगोही, जनपद शाहजहांपुर, उ०प्र०)

विद्युत, एथेनॉल, सफेद दानेदार चीनी के उत्पादनकर्ता।



चीनी मिल क्षेत्र एवं गन्ना उत्पादकों की सेवा में निरन्तर प्रयत्नशील एवं गन्ना विकास की विभिन्न योजनाओं के सघन क्रियान्वयन हेतु संकल्पित।

डालमिया भारत शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, (शुगर एवं डिस्टिलरी यूनिट-निगोही) क्षेत्र के समस्त किसान भाईयों, जनप्रतिनिधियों को डालमिया प्रबन्धतंत्र की ओर से

'गणतंत्र दिवस' की हार्दिक शुभकामनाएं।



कुलदीप कुमार

उप अधिशासी निदेशक

डालमिया भारत शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०
(शुगर एवं डिस्टिलरी यूनिट-निगोही)

कृषक बन्धुओं से अनुरोध है कि चीनी मिल को साफ व ताजा गन्ना ही आपूर्ति करें। कृषक भाई अपना-अपना बीज स्वयं रोक कर रखें जिससे बुवाई के समय बीज की परेशानी न हो। अधिक से अधिक रकबे में ट्रेंच विधि से उन्नतिशील प्रजातियों के गन्ने की बोवाई करके स्वयं व चीनी मिल को लाभान्वित करें।

दि सेकसरिया बिसवाँ शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, बिसवाँ (सीतापुर)

(आई0एस0ओ0 9001:2015, 14001:2015 एवं 22000:2018 द्वारा प्रमाणित संस्थान)

समस्त क्षेत्रवासियों, कर्मचारियों
एवं किसान भाईयों को
नव वर्ष एवं
'गणतंत्र दिवस'
की हार्दिक शुभकामनायें।



Producer of
Double Refined Sulphur Free Sugar
(Defeco-Melt Phosphotation with IER),
Ethanol and 32 MW Co-generation Power

“मृदा परीक्षण अवश्य करायें, संस्तुति के आधार पर उर्वरक लगायें”

- ❖ ट्रेन्च विधि से गन्ने की बुवाई करायें, सह-फसल के साथ दोहरा लाभ कमायें।
- ❖ पराली एवं गन्ने की पत्ती न जलायें, ट्रैश मल्चर से जुताई कर जैविक खाद बनायें।
- ❖ गन्न प्रजाति को.पी.के.-05191 की बुवाई कदापि न करें, उन्नतशील प्रजाति को. 15023, को.लख.-14201, को.शा.-13235, को.-0118 एवं को.-0238 को अपनायें।

रमेश चन्द्र सिंघल
(मुख्य अधिशासी)

अपनी नर्सरी से खेत में लगायें गन्ना पौध

किसानों को गन्ने की पौध बाजार की नर्सरी से मिल जाती है। लेकिन जब किसान खेती करता है और खेत में बहुत सारी जगह गन्ने की पौध नहीं लग पाती है, उस जगह किसान खुद अपनी पहले लगाई गई नर्सरी के पौधे उन खाली स्थान में लगा सकता है। उस समय बाजार में लगभग पौध का स्टॉक खत्म हो जाता है और किसानों को नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान को अपनी भूमि के अनुसार पहले से ही गन्ने की पौध तैयार कर रख लेनी चाहिए। किसान, बस कुछ सावधानियों के साथ और सीमित साधनों की मदद से घर पर ही आसानी से गन्ने की नर्सरी तैयार कर अपने खेतों से गन्ने



की अच्छी फसल प्राप्त कर कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।

किसान को अच्छी तरह से गन्ने की पौध तैयार करने के लिए जिन साधनों की जरूरत होगी उनमें गन्ना बड कटर, आंख वाली गन्ने की पेड़ी, शुगर केन के लिए प्लास्टिक गिलास या छोटे पॉलीथीन बैग और अच्छा ठंडा वातावरण वाला स्थान आदि शामिल हैं।

बड गन्ना बड कटर

यह लोहे तथा लकड़ी से बना एक औजार होता है। यह गन्ने के आंख वाले भाग अलग करता है। इसे शुगर केन कटर मशीन या शुगरकेन बड चापर भी कहते हैं। गन्ने के बीज वाला भाग अलग किया जाता है। गन्ने का पौधा इसी भाग से अंकुरित अथवा उपचारित होता है। गन्ना किसान तैयार फसल में से अच्छे गन्नों का चयन करते हैं और उसका डंठल काटकर उगाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने इसे और आसान कर दिया है।

वैज्ञानिकों ने गन्ने की गांठ को चिप्स के आकार में काटा और फिर उसे कप में

उगाया। 25 से 35 दिनों में तैयार बिरवे को फिर खेत में बो दिया। इस समय एक हेक्टेयर क्षेत्रफल उगाने के लिए करीब 80 किंवा 80 गन्ने की जरूरत पड़ती है, जबकि नर्सरी में तैयार बिरवे से इतने बड़े खेत में सिर्फ दो किंवा दो गन्ने से बुआई संभव है। इससे गन्ने की बुआई की लागत 50 फीसदी घटी है। पौध लगाए गए खेत के अच्छे प्रबंधन से पौध जीवितता दर को 90 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। अच्छे किस्म के गन्ने की प्रति बीघा में 1500 से 2000 पौध लग जाती है। एक एकड़ के लिए 500 से 750 तक के पौधे लगाकर रखने चाहिए।

प्लास्टिक का गिलास

किसान यदि कम स्तर पर गन्ने की पौध तैयार करता है तो 1000 से 1500 पौधे प्लास्टिक गिलास का उपयोग कर तैयार करता है। यदि किसान अधिक क्षेत्र में गन्ने की पौध तैयार करता है, तो इसके लिए खेत में गन्ने की बड़ी-बड़ी गन्ना क्यारी भी बना सकता है। प्लास्टिक गिलास बाजार में 25 से 30 रुपये में लगभग 100 के हिसाब से मिल जाता है।

गन्ने का बीज उपचार

गन्ने की आंख लगाने से पहले उसको उपचारित भी कर सकते हैं। इसके लिए किसान कोई भी जैविक खाद तरीका या रासायनिक दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। उपचारित विधि में कार्बेण्डाजिम अथवा मैकोजेब का उपयोग कर सकते हैं। नर्सरी बनाने के लिए रोगरहित बीज गन्ना लिया जाता है। फिर एक आंख के बीज टुकड़े काटकर उन्हें 0.1 प्रतिशत कार्बेण्डाजिम के घोल में 1 मिनट तक डुबोकर क्यारियों में बिजाई कर लें। क्लोरपायरीफॉस या

गन्ने की नर्सरी/पौध

- ❏ नर्सरी लगाने से पूर्व पूर्ण योजना के अनुरूप गन्ने की पौध तैयार करनी चाहिए। इसमें सही बीजों का चयन कर पौधों की अच्छी देखरेख आदि शामिल हैं।
- ❏ गन्ना बड कटर से गन्ने की आंख को काटकर तैयार कर लें।
- ❏ प्लास्टिक गिलास में या खेत में गन्ना पौध बेड विधि उपचारित मृदा और गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाकर तैयार कर लें।
- ❏ अब प्लास्टिक गिलास को आधा भाग उपचारित मृदा से भर दें।
- ❏ आधे भरे हुए भाग के ऊपर गन्ने की आंख वाला हिस्सा ऊपर की ओर रखकर बाकी भाग को भी भर दें।
- ❏ अब सभी प्लास्टिक गिलासों को छायादार स्थान पर रख दें और तापमान बनाए रखने के लिए पॉलीथीन से ढक दें।
- ❏ 6 से 7 हफ्ते बाद पौध को खुरपी से निकालकर पूर्व से ही सिंचित खेत में लगा दिया जाता है। कुछ पौध को नर्सरी में ही छोड़ दें, जिससे बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सके।
- ❏ इस प्रकार से तैयार गन्ने के पौधे से 20 दिनों के अंतराल में पूर्ण रूप से उगकर दिखाई देने लग जाते हैं।
- ❏ पौध लगाने के लिए शाम का समय उपयुक्त रहता है।

इमिडाक्लोप्रिड 1 मि.ली. प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर नर्सरी की क्यारियों पर छिड़काव करें।

गन्ने की पौध की मृदा

पौध तैयार करने के लिए मृदा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिसके लिए गोबर की सड़ी हुई खाद और हल्की मृदा चाहिए। गोबर की सड़ी हुई खाद पानी को अच्छी तरह से अवशोषित कर लेती है और गन्ने की पौध निकलने में आसानी होती है। प्लास्टिक के गिलास में गोबर की सड़ी हुई खाद से गन्ना पौध की वृद्धि अच्छी होती है और जड़ें भी अच्छी फैलती हैं।

सीसीटीवी कैमरे लगाकर अधिकारियों को दें यूआरएल लिंक

जिलाधिकारी शामली जसजीत कौर ने जनपद की शामली, ऊन व थानाभवन चीनी मिलों के प्रतिनिधि के साथ मीटिंग में पेराई सत्र 2021-22 के बकाया गन्ना भुगतान की समीक्षा की। इस दौरान जिला गन्ना अधिकारी विजय बहादुर सिंह ने बताया कि शामली चीनी मिल ने 374.65 करोड़ के सापेक्ष 249.29 करोड़ का गन्ना भुगतान किया है। ऊन चीनी मिल ने 337 करोड़ के सापेक्ष 314.17 करोड़ एवं थानाभवन मिल ने 439.99 करोड़ के सापेक्ष 342.55 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान किया है। शामली मिल पर 125.38 करोड़, ऊन पर 22.82 तथा थानाभवन चीनी मिल पर 97.43 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान है।

जिलाधिकारी ने पेराई सत्र 2021-22 के भुगतान की स्थिति को देखकर कड़ा रोष प्रकट किया। जिसके उपरांत चीनी मिल ऊन द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा माह दिसम्बर में पेराई सत्र 2021-22 का समस्त अवशेष देय का भुगतान कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने थानाभवन एवं शामली को पेराई सत्र 2021-22 के



अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। पेराई सत्र 2022-23 में 26 दिसंबर तक चीनी मिल शामली ने 25.40 लाख कुंतल, ऊन चीनी मिल ने 29.52 लाख कुंतल तथा थानाभवन मिल द्वारा 45.59 लाख कुंतल गन्ने की पेराई गई है।

जिलाधिकारी ने चीनी मिलों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि यदि उनके क्षेत्र में कोई अवैध गन्ना खरीद की घटना संज्ञान में आती है तो वे तत्काल संबंधित

सचिव व ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को अवगत कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही, जिला गन्ना अधिकारी को अवगत कराये। जिलाधिकारी द्वारा चीनी मिलों में प्रदूषण रोकथाम हेतु स्थापित ईटीपी प्लांट्स पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर उक्त कैमरों का यूआरएल लिंक उपलब्ध कराने के लिए चीनी मिलों का निर्देश दिए।

बंद छाता शुगर मिल 550 करोड़ की लागत से होगी शुरू



पेश किया। बजट भाषण में उन्होंने छाता समेत प्रदेश की छह अन्य मिलों के पुनर्निर्माण के लिए पांच हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। धन स्वीकृत होते ही कार्य शुरू हो जाएगा।

छाता शुगर मिल की शुरुआत वर्ष 1978 में क्षेत्रीय विधायक बाबू तेजपाल ने कराई थी। यह मिल आगरा मंडल की इकलौती मिल थी जिसकी कुल क्षमता 1250 टीसीडी थी। तत्कालीन मायावती सरकार ने 2008 में इसे बंद करा दिया।

छाता शुगर मिल और डिस्टलरी प्लांट निर्माण पर करीब 550 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसकी डीपीआर नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज की टीम ने तैयार कर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण को सौंप दी है। मंत्री ने बताया कि मिल की डीपीआर मिल गई है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 239 करोड़ रुपये की लागत से मिल का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। मिल में एथनाल प्लांट होगा जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। दूसरे चरण में करीब 310 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष मिल को शुरू कराने की घोषणा के बाद विधानसभा में अनुपूरक बजट

गन्ना मंत्री ने बताया कि मिल के आधुनिकीकरण के अलावा सरकार ने पांच साल में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उत्पादकता 81.5 टन से बढ़ाकर 84 टन करने का लक्ष्य रखा है। इसी अवधि में चीनी का पड़ता 11.46 फीसद से बढ़कर 11.56 फीसद करने का लक्ष्य रखा है। शुगर टूरिज्म को बढ़ावा, गन्ना किसान संस्थान में शुगर म्यूजियम, चीनी मिलों के लिए विक्रय केंद्रों की स्थापना और गुड़ महोत्सव का आयोजन आदि योजनाएं हैं। केबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 से अब तक 1.75 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान कर नया रिकॉर्ड कायम किया है।

तहसीलों में बनेंगे बायो फ्यूल और कंप्रेसड गैस

अब पराली वायु प्रदूषण नहीं बल्कि किसानों के लिए आमदनी का स्रोत बनेगी। यह जलेगी जरूर, लेकिन राख की बजाय कोयला बनकर किसानों को लाभ पहुंचाएगी। यूपीनेडा की एक योजना में पराली से बायो कोल तैयार किया जाएगा। प्लांट लगाने वाले निवेशक को किसान पराली बेचेंगे और फिर उससे तैयार होने वाली बायो कोल का उपयोग फैक्ट्रियों में किया जाएगा।

जिन फैक्ट्रियों में कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वहां 20 फीसदी तक पराली से तैयार फ्यूल का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही कंप्रेसड बायो गैस (सीबीजी) और बायो डीजल और बायो एथेनॉल प्लांट बनाने के प्लांट तैयार होंगे। तीनों ही योजनाओं में अधिकतम अनुदान 20 करोड़ तक दिया जाना निश्चित किया गया है। खेतों में जैसे तो पराली धान के अलावा मक्के और बाजरे की फसल में भी काफी पराली का उत्पादन होता है। कोई उपयोग नहीं समझकर किसान खेत में ही पराली को जला देते हैं। इससे खेत की उर्वरक क्षमता पर तो असर पड़ता ही है साथ ही पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कई अभियान और सख्ती के बावजूद पराली जलाने पर रोक नहीं लगी।

इस पर यूपीनेडा की ओर से पराली का प्रयोग बढ़ाने के लिए बायोकोल प्लांट तैयार किए जाएंगे। इसको लेकर योजना के तहत निवेशकों को अनुदान मिलेगा। किसानों को भी प्लांट तक पराली लाने के लिए संसाधनों को लेकर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए हर तहसील में जमीन की तलाश होगी। एसडीएम स्तर से यह



कितना किस पर अनुदान

योजना	अनुदान
बीसीजी	75 लाख रुपये प्रति टन
बायोकोल	75 हजार रुपये प्रति टन
बायो एथेनॉल	03 लाख रुपये किमी की दर

क्षमता के अनुसार भूमि की आवश्यकता

- 10 एकड़ भूमि जैव ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए
- 25 एकड़ भूमि दस टन क्षमता के सीबीजी प्लांट के लिए
- 1.5 एकड़ भूमि बायो डीजल और बायो एथेनॉल प्लांट के लिए
- 02 एकड़ भूमि प्रतिदिन 100 टन उत्पादन क्षमता के बायो कोल प्लांट के लिए

कार्रवाई की जाएगी। निवेशकों को प्रति एकड़ एक रुपये लीज पर भूमि आवंटित की जाएगी। इसी प्रकार बाकी दो योजनाओं में भी भूमि की तलाश और योजना का लाभ किसानों को दिया जाएगा। बायो गैस प्लांट में गोबर और सड़े गले खाद्य पदार्थों का प्रयोग होगा।

कानपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन <http://onliupneda.in/app/> पर करें। राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 लागू होने के पर नेडा की इन तीनों योजनाओं को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। एसडीएम के माध्यम से भूमि चिन्हित की जाएगी। उसके बाद प्लांट लगाने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।



त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.

शुगर यूनिट चन्दनपुर, जनपद-अमरोहा



गली गली में तिरंगा लहराएंगे । गणतंत्र दिवस का यह पर्व हम शान से मनाएंगे ।।

त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० शुगर यूनिट-चन्दनपुर द्वारा गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

- ❖ आगामी गन्ना बुवाई में क्षेत्र के लिए लाभकारी गन्ना प्रजातियां कोजा, 88, को. 118, को. 98014, कोजा.85 व को. 15023 की ही बुवाई करें।
- ❖ अपने गन्ने के रकबे में 50 प्रतिशत रकबा क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रजाति कोजा 88 का अवश्य रखें और सफाई में सहूलियत का लाभ लें।
- ❖ भूमि का शोधन अवश्य करें। आखिरी जुताई पर ट्राइकोर्डर्मा 1ली./किलो प्रति बीघा के हिसाब से कल्चर बनाकर प्रयोग करें।
- ❖ रोगो से बचाव के लिये बोने से पहले गन्ना बीज टुकड़ों को थायोफिनेट मिथाइल का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से शोधन करें और फसल में लगाने वाले सभी रोगों से फसल को बचायें।
- ❖ भूमिक की उर्वराशक्ति बढ़ाने के लिये बायोकम्पोस्ट/गोबर की खाद 25 कु. प्रति बीघा प्रयोग करें, साथ ही साथ काला सोना (ब्यायलर की राख) 25 कुं० प्रति बीघा भी खेत में डालें।
- ❖ भूमि का उपजाऊन बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष हरी खाद (ढेंचा) को गन्ने के साथ गन्ने की लाइनो के बीच में 4-5 किलो प्रति बीघा बीज दर से लगाकर 45-60 दिन बाद मिट्टी में मिला दें।
- ❖ अधिक पैदावार लेने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 5 फिट से अधिक रखें और ट्रेन्च विधि से ही बुवाई करें।
- ❖ गन्ने की लाइनों के बीच की दूरी बढ़ाकर (5 फिट) छोटा ट्रैक्टर और छोटे कृषि यंत्रों का खेती में प्रयोग बढ़ायें जिससे खेती में लागत कम होगी और पैदावार बढ़ेगी।
- ❖ चीनी मिल को हमेशा साफ ताजा और अच्छी तरह छिला हुआ गन्ना ही आपूर्ति करें। जड़ों की सफाई दरांती से करें।
- ❖ पराली व पत्ती खेत में न जलायें इसके लिये मल्चर का प्रयोग कर कम्पोस्ट बनाकर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ायें।
- ❖ त्रिवेणी स्वास्थ्य परियोजना के तहत ग्रामों में संचालित मोबाइल चिकित्सा डिस्पेन्सरी का लाभ लें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें।



निवेदक
आमोद कुमार शर्मा
उपाध्यक्ष (शुगर)

www.jrseamless.com



JR SEAMLESS PVT. LTD.

ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018
WELL KNOWN TUBE AND PIPE MAKER



Manufacturers of

ERW BOILER TUBES (IBR),
AIR PRE HEATER TUBES,
(APH TUBES BS 6323 PART V)
CORTEN STEEL (ASME SA 423)



CARBON STEEL SEAMLESS PIPES (IBR)
SEAMLESS BOILER TUBES (IBR)
ALLOY STEEL SEAMLESS PIPES & TUBES (IBR)
RIFLE TUBES IN VARIOUS GRADES

Our unit and products are approved by

NATIONAL FEDERATION OF COOPERATIVE SUGAR FACTORIES LIMITED (NFCSF)

VASANTDADA SUGAR INSTITUTE (VSI)

Contact Us :-

Narender Agarwal
Cell: +91 - 9849088662
Email : najrspi@gmail.com

Mahender Agarwal
Cell: +91 - 9985191000
Email : mahender@jrseamless.com

Factory : Sy. No. 129, 130, 131,
Chegunta (V & M), Medak District,
Telangana - 502255, India

Mahender Agarwal
Cell: +91-9246531758
Email: mahender@ihmvalves.com

Rajender Agarwal
Cell: +91-9848031081
Email: ihm@ihmvalves.com



IHM VALVES PVT. LTD.

VALVES • FITTINGS • PIPES



5-1-494, HILL STREET, RANIGUNJ, SECUNDERABAD, TELANGANA - 500003, INDIA

Our unit and products are approved by
NATIONAL FEDERATION OF COOPERATIVE SUGAR FACTORIES LIMITED (NFCSF)

Authorised Stockists :



Manufacturer of
Forged Fittings
Flanges
Buttweld Pipe Fittings
etc. **IBR Approved**



JR FORGINGS

AN ISO 9001-2015 COMPANY



Our unit and products are approved by
NATIONAL FEDERATION OF COOPERATIVE SUGAR FACTORIES LIMITED (NFCSF)

Contact Us :-

Narender Agarwal
Cell: +91 - 9849088662

Mahender Agarwal
Cell: +91 - 9985191000

Works : 39/A/1, IDA, Balanagar,
Hyderabad, Telangana - 500037, India

Email : jrforgings@gmail.com

Email : mahender@jrforgings.com

Web.: www.jrforgings.com

किसानों ने शुरू की हाईड्रोपोनिक खेती

सहारनपुर के किसानों ने बड़ी पहल करते हुए पश्चिमी देशों में अपनाई जा रही हाईड्रोपोनिक तकनीक से होने वाली खेती को अपना लिया है। सहारनपुर के ब्लाक नांगल के गांव बड़हेड़ी कौली निवासी 23 वर्षीय युवा किसान और केवल 12वीं पास अनमोल चौधरी और उनके बड़े भाई विपिन चौधरी ने एक साल पहले हाईड्रोपोनिक तकनीक से बर्गर में इस्तेमाल होने वाले सलाद पत्ते की खेती की शुरुआत की है। उन्होंने आज संवाददाता को बताया कि वह सलाद पत्ते को सहारनपुर और देहरादून के रेस्टोरेंट को सफ़ाई करते हैं। जिससे उन्हें हर माह 40 से 50 हजार रुपए मिल जाते हैं। इससे घर का खर्च आराम से चलने लगा है। उन्होंने बताया कि उनके इलाके में गन्ने की फसल ज्यादा होती है, लेकिन कीट नाशकों के इस्तेमाल से जमीन बर्बाद हो रही है और उनके क्षेत्र की बजाज चीनी मिल किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान भी नहीं कर रही है। उन्होंने यू-ट्यूब के जरिए इस नई तकनीक को जानने का काम किया।

उन्होंने सहारनपुर के उपनिदेशक कृषि डा. राकेश कुमार और इसी विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की। दोनों ने उन्हें इस खेती को करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। उपनिदेशक कृषि ने बताया कि कम जमीन वाले किसानों के लिए यह खेती बेहद लाभकारी है। किसान इस तकनीक को अपनाकर खेती में अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं।

डॉ. कुमार ने बताया कि पांच से छह इंच वाले पौधे पर प्रति वर्ग एक रूपया से भी कम खर्च आता है। परंपरागत तकनीक से ये फसलें उगाने की तुलना में हाईड्रोपोनिक तकनीक के कई लाभ हैं। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में उन क्षेत्रों में पौधे या फसलें उगाई जा सकती हैं जहां जमीन की कमी है अथवा मिट्टी उपजाऊ नहीं है। इस विधि में खनिज के घोल की कुछ बूंदें ही काफी होती हैं और पानी का इस्तेमाल भी परंपरागत खेती की तुलना में 20 फीसद ही होता है। खनिज घोल में जो पोषक तत्व मिले होते हैं उसमें फासफोरस, नाइट्रोजन, पोटैश, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन मिले होते हैं। डॉ. कुमार का कहना है कि शुरू में इसे लगाने में खर्च ज्यादा आता है लेकिन बाद में यह बेहद ही सस्ती पड़ती है। उन्होंने बताया कि उनका विभाग किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हाईड्रोपोनिक तकनीक को अपनाकर सब्जियां जैसे रंगीन शिमला मिर्च, चाइनीज खीरा, चैरी टमाटर, स्ट्रॉबेरी और अन्य पत्ते वाली सब्जियां उगाते हैं तो उन्हें कम लागत में ज्यादा लाभ मिलेगा। इस खेती के लिए पानी, पोषक तत्व और सूर्य का प्रकाश जरूरी है।

बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती आबादी की वजह से फसल और पौधे के लिए जमीन की कमी होती जा रही है ऐसे में किसानों को पौधे या फसल उत्पादन के लिए हाईड्रोपोनिक तकनीक को अपनाना चाहिए। इन फसलों के लिए 15 से 30 डिग्री तापमान और 80 से 85 फीसद की आर्द्रता में आसानी से उगाया जा सकता है। कृषि उपनिदेशक के मुताबिक टमाटर छोटे-छोटे आकार में गुच्छों में लगते हैं। टमाटर की यह प्रजाति बेल वाली प्रजाति के नाम से जानी जाती है। इसमें छोटे-छोटे आकार के टमाटर लगते हैं। (विशाल अदलखा)



गन्ना किसानों को मिलेगी 24 घंटे सुविधा

प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस टोल-फ्री कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना विकास विभाग के मुख्यालय पर इस कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कॉल सेंटर के कार्मिकों द्वारा किए जा रहे कार्यों में प्रगति लाने और सुझावों को लेकर कंट्रोल रूम को एन. कम्प्यूटिंग सिस्टम, इ.पी.बी. एक्स, इन्टरकॉम और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है, जिससे अब टोल-फ्री नम्बर 1800-121-3203 पर अनुभवी कार्मिकों द्वारा गन्ना किसानों को 24 घंटे सहायता प्रदान की जाएगी। कॉल सेंटर के बारे में जानकारी देते हुए विभाग के अपर मुख्य

सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि टोल-फ्री कंट्रोल रूम के कार्मिकों की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ किए जाने के लिए कंट्रोल रूम को उच्च तकनीकी सुविधाओं से जोड़ा गया है, जिसके 24X7 गन्ना किसानों की सहायता की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में टोल फ्री नम्बर पर कॉल करने वाले गन्ना किसानों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए यहां कार्मिकों के अवकाश की अवधि में कार्य करने के लिए दक्ष और अनुभवी कार्मिकों की बैकअप टीम का गठन भी किया गया है। उन्होंने बताया कि किसान गन्ने की खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के लिए विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 पर और सर्वे, सट्टा, कैलेंडर पर्ची एवं गन्ने की खेती से जुड़ी नवीनतम जानकारियों से सम्बन्धित जानकारी और सुझाव पा सकेंगे। विभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएंगे। इन तकनीकी व्यवस्थाओं से किसानों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और उनके आने जाने वाले समय और पैसे की बचत होगी।





Consultancy Services for Supply, Erection, Commissioning & Installation. Maintenance, Repair Services & Spare Parts of Boiler Feed Pumps.

FIELD SERVICE

Our Overall Quick Response Capabilities:

- *Emergency Service
- *On-Site Repair
- *Scheduled maintenance during plant shutdowns with quick turnaround
- *Installation / Start-Up / Commissioning
- *System and Flow Analysis
- *Performance Certification
- *Diagnostic Surveys & Troubleshooting Annual Maintenance Contracts
- *Vibration Analysis
- *Preventative Maintenance Contracts
- *Rotating Equipment Alignment
- *Spare Part Management and Inventory Analysis
- *Maintenance Training
- *Extended Warranties (Up to 3 years)
- *Root Cause / Failure Analysis

We Also Deal In

- *Solutions to all Pumping Requirements
- *Refurbishment of Stationary & Rotary Components
- *Specialized & Customised Projects
- *High Precision Components

When BOILER FEED PUMPS are critical to the operation of your plant, it is important to work with an experienced Field Service Team & Field Service Technicians should possess the skill of performing and supporting engineered pump servicing, installations and startups.

Needless to mention Prompt Consultants expert have extensive cross-OEM knowledge, enabling them to work on many pump makes and models & we are committed to a proactive partnership with you in perfecting this mission.



Prompt
CONSULTANTS

Please Mail Your Requirement To
ypd@promptconsultants.in
or Feel Free To Call On
+91 9766622315

Additional Supply and Services offered

Mechanical

- Supply of Pumps (Spire, Wilo, KSB)
- Supply of mechanical seals (Eagle Burgmann, Sealmatic)
- Supply of industrial valves (KSB, Pascal, Normex, Lehry)
- Supply of SS pipes and fittings (Viega)
- Supply of fasteners, foundation bolts

Electric

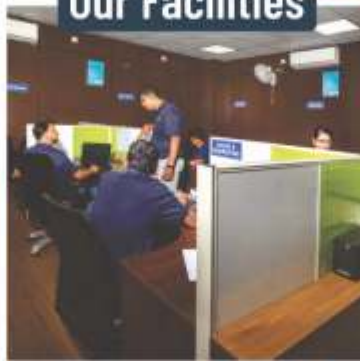
- AC drives and motion control system
- VFD installation and commissioning on Blowers, conveyors, Industrial fans, Agitators etc.
- Supply and commissioning of AC drive panels.
- Range from 0.5kW to 2000kW ratings of Brands such as L&T, Siemens, Allen Bradley, Mitsubishi, Delta, ABB etc.

- Supply, Installation and commissioning of Synchronization panels
- Energy management system.

Instrumentation

- Design Engineering, configuration, Supply, Installation and commissioning for PLC, HMI, SCADA, field instruments, Control panels.
- Software development, programming, onsite services.
- Engineering consultation for Turnkey projects (Instrumentation & Electrical)
- Wireless, RFID and IOT based solutions.
- Operator and programming training for PLC, HMI and SCADA
- Migration Services
- Consultancy and support for project documentation.

Our Facilities



Plot no. 52/2, F II Block,
Near Wondor Car service centre,
Telco road, Pimpri MIDC ,
Pune - 411 018



ypd@promptconsultants.in
sales@promptconsultants.in



www.promptconsultants.in



(020) 4003 3524



(+91) 9766 622 315
(+91) 9145 490 011

किसानों को 8 चीनी मिलों ने किया 668 करोड़ भुगतान

मुजफ्फरनगर में करीब 2 लाख हेक्टेअर भूमि कृषि योग्य है। जिसमें से 2020-21 के दौरान 1.73696 लाख हेक्टेयर भूमि में लगभग 1608 लाख टन गन्ने का उत्पादन किया गया। जनपद के किसानों की 8 चीनी मिलों से गन्ना मूल्य के रूप में प्रति वर्ष लगभग 3 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। गत वर्ष 3100 करोड़ किया गया।

जिला गन्ना अधिकारी डॉ. आर. डी. द्विवेदी ने बताया कि मौजूदा पेराई सत्र में जिले के गन्ना किसानों को 668 करोड़ से अधिक का भुगतान हो चुका है। उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर को टिकौला चीनी मिल ने 28.52 करोड़ का भुगतान किया। टिकौला चीनी मिल मौजूदा सत्र में 165 करोड़ का भुगतान किया है। मुजफ्फरनगर जिले के टिकोला शुगर मिल ने इस सीजन में सप्ताह के अंतराल में ही गन्ना किसानों को उनके गन्ने का भुगतान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है वहीं पिछले सीजन में भी जिले के मिलों में गन्ना भुगतान में प्रथम स्थान पर रहा था।

योगी सरकार के 14 दिन में गन्ना भुगतान के वायदे पूरा कर करते हुए एक कदम आगे जा कर मात्र 8 दिन में ही किसानों को उनके गन्ने का भुगतान देकर एक मिसाल कायम की है। मिल के डायरेक्टर निरंकार स्वरूप ने बताया कि टिकोला मिल ने इस वर्ष का पेराई सीजन में 17 दिसम्बर 2022 से 23 दिसम्बर 2022 तक का भुगतान



दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को कर दिया है।

8 नवंबर 2022 को मिल में पेराई प्रारंभ किया था। किसानों को 8 दिन के अंतराल में ही बराबर भुगतान दिया जा रहा है। इस प्रकार टिकोला शुगर मिल 8 दिन के अंतराल में किसानों को गन्ना भुगतान कर एक रिकॉर्ड कायम करते हुए योगी सरकार के वायदे से एक कदम आगे जा कर पूरा कर रहा है। गन्ना अधिकारी ने बताया कि टिकोला शुगर मिल इस सीजन में गन्ना किसानों को समय से पहले भुगतान कर रहा है। जो अच्छा कदम है। टिकोला शुगर क्षेत्र के गन्ना किसान समय से पहले भुगतान मिलने के कारण काफी खुश है। जिले में गन्ना भुगतान में पिछड़े रहे कुछ अन्य गन्ना मिलों के लिए भी टिकोला शुगर मिल प्रेरणा बन गया है।



डायरेक्टर निरंकार स्वरूप ने अपर मुख्य सचिव लखनऊ व आयुक्त गन्ना

विभाग लखनऊ को 30 दिसंबर तक के भुगतान करने की जानकारी पत्र भेज कर दी है। गौरतलब जनपद में पिछले दो दशक से गन्ना किसानों को गन्ने भुगतान के लिए धरने, प्रदर्शन, घेराव, आदि करने पड़ते थे जिसमें सरकार व अधिकारियों का बहुत सिर दर्द होता था टिकोला शुगर मिल के 8 दिन में भुगतान होना अधिकारियों व सरकार लिए भी राहत भरा कदम है भुगतान में पिछड़े रहे शुगर मिलों को भी उदाहरण है।



With best compliments from

L.H. SUGAR FACTORIES LTD.

MAKING LIFE SWEETER AND BRIGHTER

(Established in 1909)

Regd. Office & Work : Civil Lines. Pilibhit (U.P)-262001

Tel. : (05882)- 255867, 256053 Fax-(05882)-255518

Email-mail@lhsugar.com

अतिरिक्त गन्ने को एथेनॉल में बदलने को प्रोत्साहन



साध्वी निरंजन ज्योति

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि सरकार चीनी मिलों को चीनी के अधिक उत्पादन की समस्या को दूर करने के लिए अतिरिक्त गन्ने को एथेनॉल में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री निरंजन ज्योति ने कहा कि सामान्य चीनी सीजन में लगभग 320-360 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि घरेलू खपत 260 लाख टन होती है, जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में अधिशेष स्टॉक होता है। यह अतिरिक्त स्टॉक धन की रुकावट का कारण बनता था और चीनी मिलों की तरलता को प्रभावित करता था जिसके परिणामस्वरूप गन्ना बकाया के भुगतान में देरी होती थी और गन्ना बकाया जमा होता था। उन्होंने कहा कि, 2022-23 में लगभग 45-50 लाख टन अतिरिक्त चीनी को एथेनॉल में बदलने का लक्ष्य है।

मंत्री ने कहा कि 2025 तक 60 एलएमटी अतिरिक्त चीनी को एथेनॉल में बदलने का लक्ष्य रखा गया है, जो अधिशेष चीनी की समस्या को हल करेगा। मिलों की तरलता में सुधार करेगा जिससे किसानों के गन्ना बकाया का समय पर भुगतान करने में मदद मिलेगी। चीनी मिलों की तरलता की स्थिति में सुधार करने और उन्हें किसानों के गन्ना बकाया का समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं।

आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा 20

प्रतिशत एथेनॉल-मिश्रित ईंधन

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत 20 प्रतिशत एथेनॉल-मिश्रित ईंधन लॉन्च करने के लिए तैयार है और यह अगले महीने से चुनिंदा आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 के कर्टन रेजर में बोलते हुए कहा कि इससे (20 प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण) इंजन में बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। हमने जून 2022 में पेट्रोल का 10 प्रतिशत सम्मिश्रण हासिल किया है, जो नवंबर 2022 की समय सीमा से काफी आगे था। पुरी ने कहा, हमने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2025-2026 तक ई-20 (गैसोलीन में 20 प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण) के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुँचने के प्रयासों को भी तेज कर दिया है। वास्तव में ई-20 अगले महीने से चुनिंदा आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ प्रदूषण को कम करने के दोहरे उद्देश्य के साथ पराली (पानीपत) और बांस (नुमालीगढ़) से एथेनॉल बनाने के लिए 2जी (दूसरी पीढ़ी) रिफाइनरियों की स्थापना की गई है।



देश में बढ़ाई जा रही है एथेनॉल भंडारण क्षमता



रामेश्वर तेली

देश के विभिन्न स्थानों पर एथेनॉल भंडारण क्षमता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल में अभी औसतन 10 प्रतिशत एथेनॉल का सम्मिश्रण किया गया है। इस सम्मिश्रण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर एथेनॉल भंडारण क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 19 दिसम्बर को बताया कि एथेनॉल के सम्मिश्रण की आवश्यकताओं के अनुसार इसे रिफाइनरियों, टर्मिनलों और आपूर्तिकर्ताओं के परिसर सहित कई स्थानों पर संग्रहीत किया जाता है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार इसके भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है। उन्होंने कहा कि ओएमसीज ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2021-22 की अवधि में पेट्रोल में औसतन 10 प्रतिशत एथेनॉल का सम्मिश्रण किया गया है। इस सम्मिश्रण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर एथेनॉल भंडारण क्षमता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर यह जानकारी प्रदान की।

प्रिज्म टेक्नोलॉजी अहमदाबाद में

लगायेगी एथेनॉल यूनिट

प्रिज्म एडवांस टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज गुजरात के अहमदाबाद जिले के हलवद में 100 केएलपीडी की क्षमता वाली एथेनॉल इकाई स्थापित करने की योजना बना रहा है। प्रोजेक्ट्स टुडे में प्रकाशित खबर के मुताबिक प्रस्तावित परियोजना में तीन मेगावाट सह-उत्पादन बिजली संयंत्र की स्थापना भी शामिल होगी। प्रिज्म एडवांस टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज परियोजना के लिए वित्तीय समापन और पर्यावरण मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ठेकेदार और मशीनरी आपूर्तिकर्ता को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। कंपनी को परियोजना पर अप्रैल तक काम शुरू होने की उम्मीद है।

ब्राजील में होगा 598 मिलियन टन

गन्ना उत्पादन

ब्राजील की राष्ट्रीय आपूर्ति कंपनी कोनाब ने देश में 2022-2023 गन्ने की फसल के उत्पादन और उत्पादकता के पूर्वानुमान को अपडेट किया। कोनाब की रिपोर्ट के अनुसार देश में गन्ने का 598.3 मिलियन टन उत्पादन होने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि 2021-2022 की उत्पादन की तुलना में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। कोनाब सर्वेक्षण यह भी इंगित करता है कि ब्राजील में इस साल 36.4 मिलियन टन चीनी का उत्पादन होगा, जो 2021-22 फसल की तुलना में 4.1 प्रतिशत अधिक है। एथेनॉल उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।

चीनी मिलों के भीतर पेट्रोल पंप लगाने का सुझाव



प्रकाश नाइकनवर

चीनी कारखाने एथनॉल की खपत को बढ़ावा देने और कमाई का नया जरिया तैयार करने के लिए चीनी कारखाने अपनी उत्पादन इकाइयों को



ऊर्जा केंद्र (एनर्जी हब) में बदलने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसके तहत वे एथनॉल मिला पेट्रोल बेचेंगे, आसपास के इलाकों की रसोई गैस की मांग पूरी करने के लिए बायो-सीएनजी बनाएंगे और बेचेंगे। स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए बायो-सीएनजी और स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए कई तरह की ऊर्जा के केंद्र बनेंगे। इनके ज्यादातर ग्राहक किसान हो सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव के खाके पर उद्योग के शीर्ष अधिकारियों और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फौक्ट्रीज (एनएफसीएसएफ) जैसे संगठनों के बीच चर्चा हो चुकी है। इस्मा तो चाहता है कि पहले इस प्रस्ताव की

व्यवहार्यता और लागत के मुकाबले होने वाला लाभ जांचने का काम किसी पेशेवर एजेंसी को दिया जाए। उसके बाद ही वित्तीय सहायता और जरूरी मंजूरी हासिल करने के लिए केंद्र सरकार से बात की जाए। इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य झुनझुनवाला के अनुसार इस योजना का मकसद देश भर में गांवों के बीच में बनी 500 के करीब चीनी मिलों को पेट्रोल पंप खोलने लायक बनाना है। इन पंपों से एथनॉल मिला पेट्रोल बेचा जाएगा, घरेलू ग्राहकों के लिए बायो-सीएनजी बनाई तथा बेची जाएगी और मिल परिसर में ही ई-वाहनों की चार्जिंग के केंद्र भी बनाए जाएंगे।

अगर ग्रामीण इलाकों में ऐसे फ्लेक्स-फ्यूल पर चलने वाले वाहन मौजूद हों तो 20 फीसदी से भी अधिक एथनॉल वाला पेट्रोल इन पंपों से बेचा जा सकता है। सिंचाई पंप बनाने वाली अग्रणी कंपनियों से तो एथनॉल से चलने वाले पंप बनाने के लिए बात भी शुरू हो गई है। इन पंपों को ऐसे कारखानों से रीफिल कराया जा सकता है। झुनझुनवाला ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'हमारी मिलों में गन्ना

पहुंचाने के लिए हर साल हजारों ट्रैक्टर आते हैं। यदि उन्हें कारखाने के भीतर ही एथनॉल मिला पेट्रोल मिल जाए तो कंपनियों के लिए कमाई का अच्छा स्रोत हो सकता है। इससे एथनॉल को तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के डिपो तक पहुंचाने में होने वाला खर्च भी बच सकता है।' उन्होंने कहा कि चीनी कारखानों से 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसानों को ऐसे ईंधन की खुदरा बिक्री और दूसरी सेवाओं से बहुत राहत मिल सकती है।

एनएफसीएसएफ के महानिदेशक प्रकाश नाइकनवर ने कहा कि अभी पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का काम ओएमसी के डिपो में किया जाता है, जो काम चीनी मिलों में भी हो सकता है। इससे चीनी कंपनियों को कमाई का एक और जरिया मिल जाएगा। उन्होंने कहा, 'एनएफसीएसएफ पूरी तरह इस विचार का समर्थन करता है। उद्योग के साथ बातचीत में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कई बार इसका समर्थन किया है।'

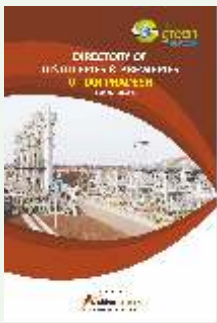
झुनझुनवाला ने कहा कि देश भर में लगी 500 के करीब चीनी मिलों में से हरेक मिल अगर अपने परिसरों में कम से कम पांच पेट्रोल पंप लगाती है तो देश में 2,500 ऐसे पंप लग जाएंगे, जो 20 फीसदी से अधिक एथनॉल वाला पेट्रोल बेचेंगे। उन्होंने कहा, 'ब्राजील में ऐसे वाहन हैं जो 100 फीसदी एथनॉल पर चल सकते हैं। हमने भी पूरी तरह एथनॉल पर चलने वाले ट्रैक्टर और अन्य मशीनें तैयार करने के लिए वाहन उद्योग से बात शुरू कर दी है।' झुनझुनवाला ने

कहा कि मांग बढ़ी तो चीनी उद्योग अपने अतिरिक्त उत्पादन में से 1 करोड़ चीनी रोककर 10 अरब लीटर एथनॉल भी बना सकता है।

फिलहाल सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20 फीसदी एथनॉल मिलाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसके लिए देश में लगभग 14.5 अरब लीटर (10.5 अरब लीटर केवल पेट्रोल में मिलाने के ही लिए) एथनॉल की उत्पादन क्षमता हासिल करनी होगी। बाकी उत्पादन स्टार्च और रसायन उद्योग के लिए अलग रखना होगा। अनुमान यह है कि 7.6 अरब लीटर एथनॉल गन्ने से बनाना होगा और 7.2 अरब लीटर एथनॉल अनाज तथा उससे इतर स्रोतों जैसे धान की ठूठ आदि से आएगा। -(संजीव मुखर्जी, बीएस)



DIRECTORY OF DISTILLERIES & BREWERIES UTTAR PRADESH



डायरेक्ट्री ऑफ डिस्टिलरी एंड ब्रेवरीज उत्तर प्रदेश

संकलन : आबकारी टाइम्स

पुस्तक के विषय

- * डिस्टिलरी और ब्रेवरी की इकाईवार जानकारियां
- * उत्पादन स्थल का नाम और सम्पर्क सूत्र
- * रजिस्टर्ड / कार्पोरेट कार्यालय का पता और सम्पर्क सूत्र
- * इकाई में कार्यरत प्रमुख पदाधिकारियों के नाम और मोबाईल नम्बर
- * इकाई में हो रहे विभिन्न उत्पादों की जानकारी
- * इकाई में स्वीकृत उत्पादन संबंधी लाइसेंस
- * इकाई में को-जेन सम्बंधी जानकारियां
- * प्रदेश में स्थापित होने वाली नई इकाईयों की जानकारी

मूल्य
रु. 500/-

आबकारी टाइम्स

485, भवानी भवन, ममफोर्डगंज, प्रयागराज -211002 (उ.प्र.)

Mob. : 73797 00003, E-mail : info@aabkaritimes.com, Web : www.aabkaritimes.com

टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बढ़ेगी किसानों की आय

किसानों की मदद के लिए जरूरी है कि खेती की लागत कम की जाए और उत्पादकता बढ़ाई जाए। इसमें रिसर्च की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह बात एनएएस (नास) के चेयरमैन, आईसीएआर के पूर्व डीजी तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के पूर्व सचिव डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने कही। वे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म रूरल वॉयस की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित कॉन्क्लेव में 'कृषि के विकास और खेती से होने वाली आय बढ़ाने में टेक्नोलॉजी की भूमिका' पर बोल रहे थे। उन्होंने जंगली गेंदा फूल का जिक्र करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती होती है और इससे जो तेल निकलता है वह 12000 से 15000 रुपये लीटर बिकता है।

उन्होंने बताया कि जब वह हिमाचल के कांगड़ा और चंबा इलाकों में आधिकारिक दौरे पर थे तब उन्हें जंगली गेंदा की खेती के बारे में पता चला। एक किसान ने बताया कि वह दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन उसे सिर्फ 15000 वेतन मिलता था। इतने कम पैसे में उसके लिए घर चलाना मुश्किल था। तब उसने नौकरी छोड़ दी और अपने प्रदेश आ गया। यहां उसने सौ-डेढ़ सौ लोगों को साथ लेकर जंगली गेंदा फूल की खेती शुरू की। शुरू में उसने उससे तेल निकाल कर बेचा तो वह 5000 से 6000 रुपए लीटर तक बिका, लेकिन बाद में इसकी कीमत 12000 से 15000 रुपये तक पहुंच गई। यही नहीं, दूसरी फसल उगाने पर किसानों को बंदरों की समस्या का सामना करना पड़ता था लेकिन गेंदा की खेती में उन्हें ऐसी कोई समस्या नहीं आई। ऑफ सीजन में भी किसान 6 महीने में 60000 रुपये की कमाई कर लेते हैं। हालांकि कमाई उनकी जमीन के आकार पर निर्भर करता है।

डॉ. महापात्र ने कहा तात्पर्य यह है कि किसानों को खेती में विविधीकरण करने की जरूरत है, क्योंकि पारंपरिक खेती से ज्यादा कमाई नहीं हो सकती है। विविधीकरण से आमदनी तो बढ़ेगी ही रोजगार भी पैदा होता है। महापात्र ने अधिक उत्पादकता के लिए तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित गन्ना ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया



डीसीएम श्रीराम लिमिटेड में शुगर बिजनेस के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोशन लाल टामक ने खेती की बाधाओं को दूर कर उत्पादकता बढ़ाने के उपायों पर बात की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ बीज का इस्तेमाल, उन पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए समान रूप से स्प्रे, उचित सिंचाई और फसलों की कटाई में मशीन के प्रयोग कुछ ऐसी बातें हैं जिनका किसानों को प्रयोग करके देखना चाहिए।

जाए तो लागत कम से कम और उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सकता है। उन्होंने बेहतर नतीजों के लिए खेती में क्लस्टर अप्रोच अपनाने की भी बात कही

टामक ने कहा जो लोग उत्पादन में अग्रणी हैं वह एक हैक्टेयर में 2500 क्विंटल गन्ना उत्पादन हासिल कर रहे हैं जबकि और औसत उत्पादकता 750 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय आधार पर उत्पादन में बहुत अंतर है। हमें यह देखना चाहिए कि समान जलवायु और मिट्टी में औसत उत्पादन इतना कम क्यों है। उन्होंने इसकी वजह गिनाते हुए कहा कि पिछले पांच से छह दशक में हमारे पास गन्ने की पांच से छह ही अच्छी किस्में आईं। हमें एक साथ कई किस्मों को विकसित करने पर काम करना चाहिए।

कामयाब किस्म 0238 को एक सुपर वेरायटी के रूप में आगे विकसित करना चाहिए। दूसरे हमें बीज और सामान्य गन्ने के बीच अंतर करना चाहिए। सामान्य गन्ने को बीज के रूप में उपयोग करना एक गलत

परंपरा है। ऐसे में हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे की कहावत चरितार्थ होती है। तीसरे गन्ना बोने की विधि बहुत अहम है। ट्रेंच विधि से उत्पादकता 10 से 15 फीसदी बढ़ जाती है। दो लाइनों के बीच की दूरी से पौधे को बेहतर धूप मिलती है और बेहतर हवा, पानी व उर्वरक मिलता है। चौथे फालिज स्प्रे के जरिये उर्वरक देने से उर्वरक की कार्यशीलता बढ़ती है। समान मात्रा में हर पौधे को उर्वरक मिलना ड्रोन से स्प्रे के जरिये संभव है। टामक ने कहा कि हमें मशीनों का उपयोग बढ़ाने की जरूरत है।

इस मौके पर एमसीएक्स के चेयरमैन और नाबाई के पूर्व चेयरमैन डॉ. हर्ष कुमार भनवाला ने किसानों की मदद के लिए सैटेलाइट के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की मदद से किसानों को अब बैंक तक जाने की जरूरत नहीं रही। उन्हें ना तो पूरे दिन की दिहाड़ी गंवाने की जरूरत है, न ही आने-जाने और खाने पर अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत है। सब कुछ एक माउस क्लिक पर उपलब्ध है।

बायोप्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर डॉ. रेणुका दीवान ने कहा कि किसानों की मुख्य चिंता खेती से होने वाला मुनाफा है। उन्होंने बताया कि खेती में जितना पैसा इस्तेमाल होता है, उसका 40 प्रतिशत बेकार चला जाता है। उपज हासिल करने में सिर्फ 60 प्रतिशत रकम का प्रयोग होता है। उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश इस नुकसान को शून्य न सही, 10 प्रतिशत पर लाने का है।

मिलेट्स की उत्पादकता बढ़ाने के हो रहे हैं प्रयास

मिलेट्स से सिर्फ रोटी ही नहीं बल्कि कई अन्य उत्पाद भी बन सकते हैं। जैसे रागी का डोसा या इडली बन सकती है, वहीं बाजरा के लड्डू बन सकते हैं, यहां तक कि बाजरा के बिस्कुट तक बनाए जा सकते हैं। खासतौर से बच्चों को ध्यान में रखते हुए मिलेट्स की टॉफी या चॉकलेट भी बन सकती है। फिलहाल लोग इसके प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं। सरकार द्वारा मिलेट्स की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे-जैसे मिलेट्स की मांग बढ़ेगी वैसे-वैसे किसानों को इनका अच्छा दाम भी मिलेगा। दुनिया के बाजार में मिलेट्स उपयोगी होगा और मिलेट्स से बने पदार्थों को मार्केट मिलेगा। इसका फायदा हमारे यहां के स्टार्टअप्स को भी होगा और इंडस्ट्री को भी होगा और अन्ततोगत्वा इसका फायदा किसानों को भी होगा।

किसानों के फायदे के लिए बनाए एफपीओ

किसान उत्पादक संगठन जिन्हें एफपीओ कहा जाता है। इनसे किसानों को फसलों को खरीद और बिक्री करने में आसानी होती है। दरअसल, भारत में करीब 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं। छोटे किसानों की अपनी आर्थिक क्षमता नहीं होती, वहीं दूसरे बड़े लोग भी ऐसे किसानों तक नहीं पहुंचते। 300 के करीब किसान यदि इकट्ठा होते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक एफपीओ बनता है। ऐसे एफपीओ के माध्यम से किसान उन्नत खेती की ओर अग्रसर हो सकता है। ये सब किसान मिलकर टेक्नोलॉजी का फायदा ले सकते हैं, एक ही प्रकार का फर्टिलाइजर खरीदेंगे, एक ही प्रकार का पेस्टीसाइड यूज करेंगे, तो ये उनको सस्ता भी मिलेगा। यही कारण है कि सरकार किसानों के फायदे के लिए एफपीओ परियोजना लेकर आई। इस पर केंद्र सरकार 6 हजार 865 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अभी तक 10 हजार एफपीओ में से 4 हजार एफपीओ रजिस्टर्ड हो चुके हैं।

एग्रीस्टैक मिशन

सरकार द्वारा डिपार्टमेंट में एग्रीस्टैक बनाया जा रहा है। यह कृषि क्षेत्र हेतु नया डिजिटल प्रयोजन साबित होगा। एग्रीस्टैक में किसान का खेत होगा और उसका सर्वे क्रमांक होगा और किसान का नाम होगा, उसका आधार कार्ड क्रमांक होगा और उसके

जी-20 कार्यक्रम

जी-20 की प्रेसीडेंसी इस बार भारत के पास है। भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए जी-20 के प्लेटफॉर्म पर देशभर में लगभग 56 कार्यक्रम होंगे। पहले इस तरीके के कार्यक्रम केवल दिल्ली तक ही सीमित होते थे लेकिन इस बार इसे देश में विकेंद्रित किया गया है। जी-20 के माध्यम से दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि जब भारत आएंगे तो वो देख पाएंगे कि भारत कैसे तरक्की कर रहा है और इस दौरान वे विभिन्न क्षेत्रों का ब्यौरा लेंगे।



खेत की जो बाउंड्री है उसका जियो टैगिंग भी उस प्लेटफॉर्म में होगा। इससे बैंक भी जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ केंद्र व राज्य सरकारें भी जुड़ी रहेंगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इसरो के साथ मिलकर एक कृषि डीएसएस बनाए जा रहे हैं जिससे कि सैटेलाइट की मदद से सर्वे कर पाएंगे। यह सैटेलाइट ऐसा होगा जो हर खेत पर 15 दिन में एक बार पहुंचेगा। एग्रीस्टैक में यदि किसी किसान का नाम दर्ज होगा तो उस किसान को बैंक से लोन मिलना भी आसान होगा।

स्वामित्व योजना से मिला मालिकाना हक

ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके पास पहले प्रॉपर्टी का कोई मालिकाना हक नहीं होता था। ऐसे में केंद्र सरकार के प्रयासों से पंचायत डिपार्टमेंट के माध्यम से सर्वे ऑफ इंडिया ने स्वामित्व योजना के अन्तर्गत ड्रोन टेक्नोलॉजी से हर गांव का सर्वे किया और जिसका मकान वहां बना हुआ है, उसकी नापतौल करके उस मकान का मालिकाना हक राज्य सरकारों के साथ उसे दिया गया।



किसान ड्रोन

ड्रोन के कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए कृषि मंत्रालय ने एसओपी जारी कर दिया है। फसलों के आकलन, भूमि रिक्तों का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन' का इस्तेमाल शुरू हो गया है। दरअसल, ड्रोन का इस्तेमाल करके अगर किसान पेस्टीसाइड या फर्टिलाइजर का छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें इसका बड़ा फायदा प्राप्त होता है, क्योंकि जितनी जरूरत है और जितने क्षेत्र में पेस्टीसाइड या फर्टिलाइजर का छिड़काव होना है वो जरूरत के हिसाब से ही होगा। साथ ही साथ पेस्टीसाइड और फर्टिलाइजर के दुष्प्रभावों से भी बचा जा सकता है। ड्रोन के माध्यम से समय की भी बचत होती है।

हरित ईंधन किसान और पर्यावरण के लिए है लाभदायक

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने एकबार कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि पांच साल बाद देश से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आपकी कारें और स्कूटर पूरी तरह हरित ईंधन (हाइड्रोजन, एथेनॉल, सीएनजी या एलएनजी) पर आधारित होंगे। वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन की महंगाई दोनों ही बेहद गंभीर समस्याएं हैं। बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है तो वहीं बढ़ती डीजल-पेट्रोल की मांग व कीमतें आम जनता को बेहाल कर रही है। जिसके निवारण में ग्रीन फ्यूएल एक अहम भूमिका निभा सकता है।

पर्यावरण व किसानों के लिए कैसे है लाभदायक हरित ईंधन

एथेनॉल, जिसको खेतों से निकली पराली, खाद्य पदार्थों के अवशेष और दूसरी कई चीजों से बनाया जाता है, वायु प्रदूषण को कम करने में काफी हद तक सहायक है। इसके साथ ही यह किसानों की आय बढ़ाने का भी काम कर रहा है। क्योंकि भारत में जहां चावल, मक्का, गन्ना और गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इनके कृषि अवशेष का निपटान भी एक बड़ी समस्या है, ऐसे में एथेनॉल उत्पादन में इन फसलों के कृषि अवशेष, जो अभी तक जलाये जाते थे, को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यही कारण है कि एथेनॉल कारखाने लगने से न सिर्फ वायु प्रदूषण, बल्कि महंगे तेल की समस्या को हल करने में भी खासी मदद मिलेगी तथा किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इसके साथ ही साथ एथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाए जाने से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। दुनिया को ग्रीन फ्यूएल का विकल्प देने में भारत की भूमिका काफी अहम हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में पर्याप्त मात्रा में धूप होती है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करने में मदद मिल सकती है।

कार्बन उत्सर्जन में भारत व अन्य देशों की स्थिति

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को आश्चस्त किया है कि 2030 तक भारत कार्बन उत्सर्जन की मौजूदा मात्रा को 33-35 प्रतिशत घटा देगा और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी हासिल

क्या होता है ग्रीन फ्यूएल

ग्रीन फ्यूएल (हरित ईंधन), ऊर्जा का वह स्रोत है जो उपयोग करने पर बहुत कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसके एक प्रकार को जैव ईंधन भी कहा जाता है। यह बायोमास यानि पौधे या शैवाल सामग्री या पशु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के विपरीत अक्षय ऊर्जा (जो प्रदूषणकारक नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायो गैस आदि) को भी हरित ऊर्जा और ईंधन का एक स्रोत माना जाता है। इसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में मान्यता मिल गयी है। इसमें बायो एथेनॉल, बायो गैस, बायो डीजल, बायो हाइड्रोजन व बायो ब्यूटेनॉल आदि आते हैं।

किण्वन विधि द्वारा बायो एथेनॉल (अक्षय ईंधन/अल्कोहल) बनाया जाता है। इस विधि में सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया



और खमीर आदि) पादप शर्करा को उपापचय कर एथेनॉल का उत्पादन करते हैं। इस विधि से गन्ना, ज्वार, मक्का, बाजरा, धान, गेहूं और दूसरे बीज-अवशेषों से भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। इसी प्रकार बायोडीजल को सोयाबीन तेल या ताड़ के तेल, वनस्पति अपशिष्ट तेलों और पशु वसा जैसे वनस्पति तेलों से प्राप्त किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूएल को पानी से बनाया जाता है। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस (सोलर एनर्जी द्वारा) करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। हाइड्रोजन एक पावरफुल ईंधन है, जिसको काफी मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है।

ग्रीन फ्यूएल के नकारात्मक पहलू

ग्रीन फ्यूएल के सकारात्मक पहलू के साथ-साथ कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूएल की कीमत बहुत ज्यादा है। साथ ही यह अधिक ज्वलनशील होता है, जिससे सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कृषि भूमि पर खाद्यान्न उत्पादन अधिक हो, यह प्राथमिकता छोड़कर यदि बायो फ्यूएल के लिए फसलों का उत्पादन होने लगा तो भविष्य में देश की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह भी लग सकता है।

करेगा। भारत जहां प्रतिवर्ष 20.70 लाख किलो टन (प्रति व्यक्ति 1.7 टन) कार्बन उत्सर्जन करता है, वहीं अमेरिका सर्वाधिक 1.03 करोड़ किलो टन (प्रति व्यक्ति 7.4 टन) कार्बन उत्सर्जन करता है।

ग्रीन फ्यूएल के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए कदम

भारत सरकार हाइड्रोजन और अमोनिया को भविष्य के प्रमुख हरित ईंधन के रूप में मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा

ग्रीन फ्यूएल को बढ़ावा देने के अंतर्गत 75वें स्वतंत्रता दिवस अर्थात् 15 अगस्त 2021 को 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन' प्रारंभ किया गया था। जिसका उद्देश्य जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना तथा भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। इस मिशन के अंतर्गत 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन व नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से संबंधित विकास में मदद मिलेगी।

इस मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया विनिर्माता पावर एक्सचेंज से नवीकरणीय ऊर्जा खरीद सकते हैं अथवा अन्य माध्यम से अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर सकते हैं। यह नीति नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देगी, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए मूल सामग्री होगी। जिससे स्वच्छ ऊर्जा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद प्राप्त होगी। केंद्र सरकार द्वारा करीब 199 एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई है। (सुदामा भरद्वाज (वन इंडिया न्यूज))

MYCORe



माईकोर

जैव उर्वरक



जब जड़ों में हो जान
बढ़ेगी उपज,
बढ़ेगा मान

control
IMO

HYT



अधिक जानकारी
के लिए
QR-कोड
स्कैन करें

MAXYLD



मैक्सयील्ड

ज्यादा और
बेहतर उपज
के लिए



अधिक जानकारी
के लिए
QR-कोड
स्कैन करें

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
(हमारे टोल फ्री नम्बर पर)

1800-102-1022

इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम

SEMPRA



सेम्प्रा[®] ने किया कमाल



गांठों से खत्म करे मोथा

मेहनत कम,

मुनाफा मोटा



अधिक जानकारी
के लिए
QR-कोड
स्कैन करें

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
(समय टोल फ्री नम्बर पर)

1800-102-1022

इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम

जैविक खेती उत्पादन को लेकर, सही नहीं है किसानों का भ्रम

रसायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से हमारी धरती बंजर होती जा रही है। इसका असर ना सिर्फ मिट्टी की सेहत पर पड़ रहा है, बल्कि पर्यावरण और लोगों की सेहत भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अब किसान भी समझने लगे हैं कि रसायनिक खेती करने पर लागत भी ज्यादा आ रही है। सिर्फ किसान ही नहीं देश के युवा, प्रोफेशनल्स और शहरों में रहने वाले लोग भी अब जैविक खेती और इससे उपजे उत्पादों को प्रति जागरूक हो रहे हैं। कई लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़कर जैविक खेती को ही बिजनेस बना लिया है। इस सब के बावजूद आज भी कई किसानों को मन में जैविक खेती को लेकर तरह-तरह के भ्रम हैं।

कई किसान पूरी तरह जैविक खेती की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनका मानना है कि जैविक रसायनिक खेती छोड़कर खेती करने पर शुरुआती सालों में फसल की उत्पादकता कम हो जाती है। हालांकि कई राज्य सरकारें जैविक खेती करने के लिए अनुदान भी देती हैं, जिससे किसानों पर इस नुकसान को कम किया जा सके, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने (आईसीएआर) 'जैविक खेती से उत्पादन की कमी' की बात को सिर से नकार दिया है। आईसीएआर ने कुछ समय पहले ही एक रिपोर्ट जारी करके बताया था कि कैमिकल फार्मिंग के मुकाबले जैविक खेती की उत्पादकता 20 से 25 फीसदी तक ज्यादा है। इस संबंध में उसने कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं।

कई गुना बढ़ जाता है उत्पादन

पर्यावरण में हो रहे अनिश्चितकालीन बदलावों के बीच कई सालों से किसानों को जैविक खेती की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कैमिकल फ्री खेती को प्रोत्साहित करते हुए कई अभियान और योजना चलाई हैं। इसी कड़ी में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर कुछ साल पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी। इस रिपोर्ट में भारत की प्रमुख नकदी फसल- गन्ना, चावल, मूंगफली, गेहूं, फल और सब्जियों के जैविक खेती बनाम रसायनिक खेती से मिले उत्पादन के आंकड़े प्रस्तुत किए।

रसायनिक खेती बनाम जैविक खेती (फसल की उत्पादकता)			
फसल	रसायनिक खेती	जैविक खेती	जैविक उत्पादन में ग्रोथ
गन्ना (टन)	817	942	15.26 प्रतिशत
चावल (क्विंटल)	78	88	12.82 प्रतिशत
मूंगफली (क्विंटल)	14	18	28.57 प्रतिशत
सोयाबीन (क्विंटल)	51	74	45.09 प्रतिशत
गेहूं (क्विंटल)	35	45	28.57 प्रतिशत
फल एवं सब्जियां(क्विंटल)	14	15	7.14 प्रतिशत

Source:- Indian Agriculture Research Institute

उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना जरूरी

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. युद्धवीर सिंह बताते हैं कि फसल की ग्रोथ के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के लिए ऑर्गेनिक कार्बन मेन सोर्स है। इसकी कमी से पौधों का विकास थम जाता है, जिससे उत्पादन भी कम हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने पर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को भी बढ़ाया जा सकता है। कई रिसर्च में साबित हुआ है कि कैमिकल के बढ़ते इस्तेमाल से ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होती जा रही है। खासतौर पर



हरित क्रांति से पहले गंगा के मैदानी इलाकों में 0.5 फीसदी ऑर्गेनिक कार्बन मौजूद था, जो आज घटकर 0.2 फीसदी ही रह गया है। ये बंजर होती जमीन का सूचक है, जिसे जैविक खेती करके ही ठीक किया जा सकता है।



इन आंकड़ों से पता चला कि जैविक विधि से उगाए गए गन्ना की पैदावार कैमिकल वाली खेती से 15.26 प्रतिशत अधिक रहती है। इसके अलावा, जैविक विधि से चावल की 12.82 फीसदी, गेहूं की 28.57 फीसदी, मूंगफली की 28.57 फीसदी, सोयाबीन की 45.09 फीसदी और फल-सब्जियों की उत्पादकता में 7.14 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

जैविक खेती के बेमिसाल फायदे

ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यानी जैविक विधि से उगे फल, सब्जी, अनाज की कीमत कैमिकल खेती से उपजे उत्पादों की तुलना में ज्यादा होती है। जबकि कैमिकल वाली खेती की लागत ज्यादा होती है। जैविक खेती के हितैषियों का मानना है कि जैविक खेती का क्रम लगातार जारी रखने से ही अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। अब

यदि अपनी सेहत को बेहतर रखना है तो कैमिकल फ्री ऑर्गेनिक उत्पादों का सेवन करना ही होगा। यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। जैविक खेती का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे खेती की लागत कम होती है और बाजार में ऑर्गेनिक उत्पाद ज्यादा दाम पर बिकते हैं, जिससे किसानों की आय में भी ग्रोथ हुई है। जैविक खेती करने से ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी में जीवांशों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ उर्वरता भी बढ़ जाती है। जैविक खेती से जमीन में भूजल स्तर बेहतर बनता है और मिट्टी में नमी कायम रहती है। मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण भी नहीं होता और सिंचाई की कम ही आवश्यकता होती है।

दुनिया में बढ़ रही भारतीय जैविक उत्पादों की मांग

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की धरती को सबसे ज्यादा उपजाऊ बताया जाता है। देश में जैविक खेती को अब बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन युगों-युगों से यहां के किसान जैविक खेती ही करते आ रहे हैं। साल 2022 में प्रकाशित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट जर्मनी और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक रिसर्च स्विट्जरलैंड के हवाले से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया था कि साल 2014-2020 यानी 6 वर्ष की अवधि में जैविक उत्पादों की मांग 8.7 फीसदी तक बढ़ गई है, जिसमें हर साल ग्रोथ दर्ज हो रही है।

जैविक उत्पादों के वैश्विक निर्यात को लेकर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण- एपीडा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2020-21 के दौरान भारत से करीब 7,078 करोड़ रुपये के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात हुआ, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि साल 2016-17 में सिर्फ 3,05,599 मीट्रिक टन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हुआ था। इन रुझानों से ही समझ सकते हैं कि सिर्फ 4 साल के अंदर जैविक कृषि उत्पादों की डिमांड 3 गुना बढ़ गई, जिससे निर्यात भी 8,88,179.69 मिट्रिक टन हो गया है। आज अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल भी भारत की मिट्टी में उगने वाले जैविक कृषि उत्पादों के फैन हैं।

हाइड्रोजन मिशन के लिए 19500 करोड़ रुपये हुए मंजूर

सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,500 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के प्रस्ताव को 4 जनवरी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में इस योजना की शुरुआत की थी। जिनका उद्देश्य देश में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाना और हरित हाइड्रोजन बनाने में उपयोग होने वाले प्रमुख घटक इलेक्ट्रोलाइजर के विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

केंद्र ने एक बयान में कहा, 'मिशन के लिए शुरुआती व्यय में साइट कार्यक्रम के लिए 17,490 करोड़ रुपये, पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़ रुपये, अनुसंधान एवं विकास के लिए 400 करोड़ रुपये और मिशन के अन्य घटकों के लिए 388 करोड़ रुपये शामिल होंगे। इस योजना का प्रारंभिक लक्ष्य सालाना 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन तैयार करना है।

हरित हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम या साइट के लिए नीतिगत हस्तक्षेप में इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए दो



वित्तीय प्रोत्साहन प्रणाली शामिल होंगी। मिशन वास्तविक उपयोग वाले उभरते क्षेत्रों और उत्पादन की दिशा में चलाए जाने वाली पायलट परियोजनाओं का भी समर्थन करेगा। हाइड्रोजन के व्यापक उत्पादन या उपयोग का समर्थन करने में सक्षम इलाकों को 'हरित हाइड्रोजन हब' के तौर पर चिह्नित और विकसित किया जाएगा।

सरकार ने कहा कि हरित हाइड्रोजन तंत्र की स्थापना का समर्थन करने के लिए एक सक्षम नीतिगत ढांचा विकसित किया जाएगा। बयान में कहा गया है, 'एक उन्नत मानक और नियमन ढांचा भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा मिशन के तहत सार्वजनिक-निजी साझेदारी की व्यवस्था शोध एवं विकास को बढ़ावा देगी।'

149 चीनी मिलों ने निर्यात कोटा किया एक्सचेंज

देश में कम से कम 149 चीनी मिलों ने 26 दिसंबर तक 12 लाख टन से अधिक के अपने चीनी कोटे का आदान-प्रदान किया है। 4 जनवरी को यह सुविधा बंद हो जायेगी। चीनी कोटे का आदान-प्रदान करनेवाली ज्यादातर मिलें उत्तर प्रदेश और बिहार की हैं। द हिन्दू में प्रकाशित खबर के मुताबिक मिलों को 3-4 रुपये /किग्रा का प्रीमियम मिल रहा है और महाराष्ट्र और कर्नाटक में बंदरगाहों के पास स्थित मिलें कोटा खरीद रही हैं।

केंद्र सरकार ने 5 नवंबर को 60 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है, जिसे 31 मई, 2023 तक किया जा सकता है। खाद्य मंत्रालय ने प्रत्येक चीनी मिल को निर्यात कोटा आवंटित करके शिपमेंट की अनुमति दी और मिलों के बीच आवंटित मात्रा को विनिमय योग्य भी बनाया। दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी मिल जो निर्यात कोटा वापस करना चाहती है उसे 4 जनवरी से पहले ऐसा करना होगा और कोटा हर महीने आवंटित घरेलू बिक्री मात्रा के साथ समायोजित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक मिल जो निर्यात कोटा का आदान-प्रदान करती है उसे घरेलू बाजार में अपने नियमित मासिक कोटे से अधिक मात्रा में बिक्री करनी होगी। इसी तरह एक मिल जो किसी अन्य मिल से कोटा खरीदकर अधिक निर्यात करने के लिए सहमत होती है, उसे उसी मात्रा में नियमित मासिक घरेलू बिक्री आवंटन का त्याग करना होगा।



UNIVERSAL FORCES INDUSTRIES PVT. LTD.

UFI is a leading organization in providing technology for production of bio-fuels such as ethanol (sustainable green energy) to replace fossil fuels (coal, petroleum products etc.)



PROMISING STEPS TOWARDS BIOENERGY



Mr. Pradip Dhokare
Managing Director



#we ♥ biofuel



For a healthier, happier and better life, we must embrace the goodness of biofuel

- One stop solution for whole Greenfield project campus with integrated full guarantee.
- A distinct benefit of having a 100% guarantee for all sections of plant.
- Highest Performing plants with guaranteed 2 years of operational service.
- Discounted life time support for plants at fixed rates / Paid Services.
- Maximal plant security and optimal production stability at minimal cost.
- World class manufacturing infrastructure with ASME and IBR certifications.
- Instrumental Part of worlds trending technology in 2G Ethanol.
- Opportunity to have fastest delivery.



भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



- * 21+ Fuel Ethanol Plants
- * 26+ Modern Distillery
- * 12+ Biogas Plants
- * 12+ Evaporation Plants
- * 100+ Happy Customers

www.universalforces.in



SCAN FOR MORE INFO

Corporate Office:

Universal Center, Plot no. 130C, Sector no. 10, Bhosari MIDC PCNTDA, Bhosari, Pune -411026

Email: Marketing: ufisales1@gmail.com | info@universalforces.in General: contact@universalforces.in

Manufacturing Units:

Unit-I: T/3/380, Gat no. 78, Jyotibanagar, Talawade, Pune – 411062 Unit-II: C-6, Phase- I, Chakan MIDC, Pune- 410105

Phone NO: Central & Southern Regional Marketing - 9763717138 | 9284545320, North Regional Marketing (Delhi) - 9763717126

चीनी उत्पादन 3.63 % घटकर 3.45 करोड़ टन रहने का अनुमान

शुगर सीजन 2022-23 में देश का चीनी उत्पादन 3.45 करोड़ टन रह सकता है जो एक साल पहले की तुलना में 3.63 प्रतिशत कम है। चीनी उद्योग के निकाय ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन (एआईएसटीए) ने यह संभावना जताई है। भारत में चीनी का उत्पादन विपणन सत्र 2021-22 के दौरान 3.58 करोड़ टन रहा था। एआईएसटीए ने मौजूदा सत्र के अपने पहले अनुमान में कहा है कि उत्पादन में गिरावट का अनुमान होने से निर्यात भी घटकर लगभग 70 लाख टन रह सकता है।

एआईएसटीए ने कहा, वर्ष 2022-23 सत्र के दौरान महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन 1.24 करोड़ टन होने का अनुमान है जो पिछले सत्र के 1.37 करोड़



टन से कम है। इसका कारण गन्ने की पैदावार 9-10 टन प्रति हेक्टेयर कम होने का अनुमान है। इसी तरह, कर्नाटक में चीनी उत्पादन पहले के 62 लाख टन के मुकाबले कम होकर 57 लाख टन रहने का अनुमान है। इसकी वजह यह है कि राज्य में कई मिलों ने एथेनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त या नई डिस्टिलरी लगाई हैं।

उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन वर्ष 2022-23 सत्र में पिछले सत्र के 1.02 करोड़ टन की तुलना में थोड़ा अधिक बढ़कर 1.05 करोड़ टन होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती का रकबा मामूली रूप से बढ़ा है लेकिन उपज कम होने से लाभ की स्थिति बेअसर हो सकती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक देश के शीर्ष तीन चीनी उत्पादक राज्य हैं। एआईएसटीए के अनुसार, लगभग 50 लाख टन सुक्रोज का इस्तेमाल भारी शीरा, चीनी सिरप और गन्ना रस से एथेनॉल बनाने के लिए किया जाएगा। लगभग 3.45 करोड़ टन के अनुमानित उत्पादन और 60 लाख टन के शुरुआती स्टॉक के साथ, चीनी की कुल उपलब्धता 2022-23 सत्र के दौरान 4.05 करोड़ टन रह सकती है जो वर्ष 2021-22 के 4.45 करोड़ टन से कम है।

भारत ने किया 16.92 करोड़ टन चीनी का निर्यात

भारत ने चार जनवरी तक 16.92 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। इस दौरान 59,596 टन चीनी पड़ोसी चीन को भेजी गई। उद्योग संगठन आल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन (एआईएसटीए) के मुताबिक चार जनवरी तक बांग्लादेश को 1.47 लाख टन और श्रीलंका को 82,462 टन चीनी का निर्यात किया गया।

एसोसिएशन के मुताबिक एक अक्टूबर, 2022 से 4 जनवरी तक कुल 16,92,751 टन चीनी का निर्यात किया है। इसके अलावा 3.47 लाख टन चीनी का लदान किया जाना है। साथ ही 2.54 लाख टन चीनी रिफाइनरी को दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग छह लाख टन चीनी निर्यात का आर्डर मिलों के पास है।

सर्वाधिक 1.70 लाख टन चीनी का निर्यात सोमालिया को किया गया। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को 1.69 लाख टन, जिबूती को 1.50 लाख टन और सूडान को 1.37 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया। मलेशिया को 1.36 लाख टन, इंडोनेशिया को 1.18 लाख टन और सऊदी अरब को 1.08 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया।

वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों में आई उछाल

वैश्विक बाजार में चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 23 दिसम्बर (टीए-3) को, कच्ची चीनी 5.5 पाउंड प्रतिशत के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई। भारतीय निर्यातक कच्ची चीनी एक्स मिल 39000 प्रति टन और सफेद चीनी 40000 रुपये प्रति टन पर खरीद रहे हैं। वैश्विक बाजार में, 1 नवंबर से 1 अप्रैल की अवधि के लिए लगभग 40 लाख टन कच्ची चीनी और 40 लाख टन सफेद चीनी की जरूरत हैं। केंद्र सरकार ने सीजन 2022-2023 के लिए चीनी निर्यात के लिए मिल वार कोटा तकनीक अपनाई है। इसलिए, इस मौसम में कच्ची चीनी के उत्पादन में मिलों के सामने कुछ सीमाएं हैं।

वैश्विक बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुसार भारत से कुल 60 लाख टन निर्यात में से कच्ची चीनी का निर्यात लगभग 20 लाख टन किया जाएगा। वैश्विक बाजार में 23 जनवरी तक अत्यधिक कच्ची चीनी की मांग होगी। भारत सरकार और 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने की संभावना है। 15 दिसंबर तक भारतीय चीनी मिलों ने कुल 50 लाख टन निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नवंबर के अंत तक 6 लाख टन से अधिक चीनी वास्तव में निर्यात की गई है। 15 दिसंबर तक, 9 लाख टन चीनी निर्यात करने की प्रक्रिया में थी। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन का अनुमान है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह के बाद कुल 15 लाख टन चीनी का वास्तव में निर्यात किया जा सकता है।



जनवरी 2023 के लिए 22 लाख टन चीनी बिक्री कोटा हुआ जारी

खाद्य मंत्रालय ने 30 दिसंबर, 2022 को जारी अधिसूचना में जनवरी 2023 के लिए देश के 553 मिलों को चीनी बिक्री का 22 लाख टन कोटा आवंटित किया है। इस माह पिछले माह के समान चीनी आवंटन की गयी है। खाद्य मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2022 के लिए 22 लाख टन चीनी बिक्री कोटा की मंजूरी दी गयी थी। वही दूसरी ओर जनवरी 2022 की तुलना में इस बार कम चीनी आवंटित की गई है। सरकार ने दिसंबर 2022 के लिए 21.50 लाख टन चीनी आवंटित की थी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के एक ट्वीट कर भी यह जानकारी दी है।

चीनी उत्पादन में चार लाख टन की बढ़ोत्तरी

चालू पेराई सीजन 2022-23 में 31 दिसंबर, 2022 तक चीनी उत्पादन में चार लाख टन की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।



इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू सीजन में अभी तक 120.7 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है जो पिछले साल इसी समय तक 116.4 लाख टन रहा था। उत्पादन में बढ़ोत्तरी महाराष्ट्र में अधिक उत्पादन के चलते दर्ज की गई है। इस्मा के मुताबिक इस साल 509 चीनी मिलों में उत्पादन हो रहा है जबकि पिछले साल इस समय 500 चीनी मिलों में पेराई हो रही थी। महाराष्ट्र में पिछले साल की 189 चीनी मिलों के मुकाबले इस साल 196 चीनी मिलें पेराई कर रही हैं। महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन पिछले साल के 45.8 लाख टन के मुकाबले इस साल अभी तक 46.8 लाख टन पर पहुंच गया है।

उत्तर प्रदेश में अभी तक 30.9 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है जो पिछले साल का समान स्तर है। वहीं राज्य में पिछले साल की 119 चीनी मिलों के मुकाबले इस साल 117 चीनी मिलें पेराई कर रही हैं। कर्नाटक में चीनी उत्पादन मामूली रूप से बढ़कर 26.7 लाख टन पर पहुंचा गया है जो पिछले साल समान अवधि में 26.1 लाख टन रहा था। वहीं गुजरात में चीनी का उत्पादन 3.8 लाख टन रहा है।



तमिलनाडु का चीनी उत्पादन 2.6 लाख टन रहा है। चालू पेराई सीजन में इस्मा ने 365 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमाना लगाया है जो पिछले सीजन में 358 लाख टन रहा था। पिछले साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन सबसे अधिक रहेगा जबकि दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन पिछले साल से कम रहने के आसार हैं।

चीनी उद्योग में 2023 में भी विकास जारी रहेगा

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार, चीनी उद्योग के लिए 2022 में एक अच्छा साल रहा और उत्पादन में लगातार वृद्धि की राह पर है। बीक्यू प्राइम के साथ बातचीत में इस्मा के महानिदेशक संजॉय मोहंती ने कहा कि पिछला साल 111 लाख टन के रिकॉर्ड निर्यात और एथेनॉल के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ सबसे अच्छा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि 2023 में भी विकास जारी रहेगा।



एस मोहंती

सरकार ने पहले ही 60 लाख टन निर्यात की घोषणा की है। इस सत्र के लिए हमारे उत्पादन दृष्टिकोण को देखते हुए, जनवरी के अंत में अतिरिक्त चीनी निर्यात की घोषणा होने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि चीनी एक ऐसा क्षेत्र है जो 2023 में नेतृत्व करेगा। हम निवेश, जलवायु मोर्चे तथा सभी महत्वपूर्ण चीजों में नेतृत्व करना चाहेंगे। भारत का शुद्ध चीनी उत्पादन लगभग 365 लाख टन होने का अनुमान है। हमारे पास 55 लाख टन का शुरुआती स्टॉक है। उन्होंने कहा, बेहतर उपज के कारण हम उत्पादन में लगातार वृद्धि के पथ पर हैं। रकबा वही रहता है, लेकिन फसल की विविधता, बेहतर कृषि पद्धतियों आदि के कारण उत्पादन बढ़ रहा है।

सत्रवार संचालित चीनी मिलों के आयात, निर्यात, खपत आदि के आंकड़े (लाख टन में)

सत्र	संचालित कारखानें	शुरुआती सत्र में कैरी ओवर	वर्ष के दौरान उत्पादन	आयात	कुल उपलब्ध आपूर्ति	खपत	निर्यात	चीनी का अंतिम स्टॉक	चीनी का स्टॉक प्रतिशत में
2010-11	527	47.04	243.94	-	290.98	207.69	26.00	57.29	24.52
2011-12	529	57.29	263.43	-	320.72	220.000	33.90	66.82	26.32
2012-13	526	66.82	251.41	7.25	325.48	230.00	3.48	92.00	39.40
2013-14	513	92.00	243.60	11.77	347.37	244.27	27.82	75.28	27.65
2014-15	538	75.28	283.13	12.36	370.77	256.55	23.02	91.20	32.62
2015-16	526	91.20	251.25	-	342.45	248.50	16.70	77.25	29.13
2016-17	489	77.25	202.62	4.48	284.35	244.48	0.46	39.41	16.11
2017-18	525	39.41	323.28	2.24	364.93	253.90	6.32	104.71	40.23
2018-19	531	104.71	331.62	-	436.33	253.00	38.00	143.33	48.91
2019-20	464	143.33	273.85	-	417.18	253.00	59.40	104.78	33.54
2020-21	504	104.78	311.00	-	415.78	260.00	71.90	83.88	25.30
2021-22*	524	83.88	359.55	-	443.43	270.00	112.00	61.43	16.08

फरवरी 2023 में होगा भारत ऊर्जा सप्ताह



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल फरवरी में कर्नाटक में मनाए जाने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 18 दिसम्बर को हावेरी जिले के शिगागांव तालुक के कोननकेरी गांव में वीआईएन डिस्टिलरीज एंड शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड के 3,000 केएलपीडी एथेनॉल और चीनी कारखाने का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत और विदेश दोनों से लगभग 10,000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे जो ऊर्जा उत्पादन पर विचार करेंगे। भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को बेंगलुरु में आयोजित करने का फैसला किया है, जहां सबसे अधिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैं।



उन्होंने कहा कि एथेनॉल वर्तमान समय की मांग है और उन्हें स्थापित करने के लिए सरकार 6 प्रतिशत ब्याज पर सब्सिडी और 95 प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रही है। हावेरी जिले के सांकुर और हिरेकेरूर में दो एथेनॉल कारखाने काम कर रहे हैं और कुछ नये आएंगे। सरकार कारखानों को शुरू करने की अनुमति देगी क्योंकि इससे किसानों की बेहतरी, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और राजस्व में मदद मिलेगी।

अगले 50 वर्षों में जैव ईंधन की मांग बढ़ने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और ऊर्जा आपस में जुड़े हुए हैं और इन कारकों के बीच संतुलन बनाकर आर्थिक समृद्धि देखी जा सकती है। कर्नाटक एक प्रगतिशील राज्य रहा है और देश का भविष्य यहां लिखा गया है। कर्नाटक में जो सोचा और लागू किया गया, वह बाद में देश ने किया और वह इस राज्य की शक्ति है।

मिलों ने किया 45 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन

राज्य में 34 चीनी मिलों ने इस सीजन में 45 लाख लीटर से अधिक एथेनॉल का उत्पादन किया है। चीनी और कपड़ा मंत्री शंकर पाटील-मुनेनकोप्पा ने 20 दिसम्बर को परिषद में कहा कि सरकार ऐसे उप-उत्पादों से गन्ना किसानों को लाभ का प्रतिशत देने के लिए कदम उठा रही है। गन्ना मूल्य पर उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों ने राज्य सलाहकार मूल्य (एसएपी) विधेयकों को लागू किया है जो उन्हें उत्पादकों को अधिक कीमत देने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ऐसा विधेयक अभी तक नहीं है, राज्य ने उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) लागू किया है जिसका सभी मिलों द्वारा पालन किया जा रहा है।

गुड़ इकाइयों को मिलेगा 'उद्योग' का दर्जा

गुड़ और गुड़-आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग, स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बढ़ती जागरूकता और व्यापक मिलावट के कारण वाणिज्य और उद्योग विभाग को इस क्षेत्र को विनियमित करने और इसके मानकों को निर्धारित करने पर विचार कर रहा है। इस सेक्टर को 'उद्योग' का दर्जा देने के बारे में निर्णय लेने के लिए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनाई गई है। गुड़ में चीनी की तुलना में उच्च पोषण मूल्य है, इसकी खपत केवल स्थायी जीवन शैली पर बढ़ते फोकस के साथ ही बढ़ेगी। भारत गुड़ का सबसे बड़ा निर्यातक है। तीसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य होने के नाते कर्नाटक में गुड़ उत्पादन के लाभों को भुनाने की योजना बनाई जा रही है। गुड़ उद्योग को 'उद्योग' का टैग निश्चित रूप से न केवल इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने बल्कि रोजगार पैदा करने में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। यह इकाइयों को नियामक नियंत्रण में लाएगा ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और मिलावट की जांच की जा सके।

द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वाणिज्य और उद्योग विभाग ने कहा कि चीनी मिलों में बड़े पैमाने पर मशीनरी होती है, गुड़ इकाइयां बिना मशीन के पारंपरिक तरीकों से संचालित होती हैं। इस वजह से हमने इसे उद्योग नहीं माना और नवगठित औद्योगिक नीति 2020-25 के तहत गुड़ इकाइयों को कोई समर्थन नहीं दिया गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के कारण गुड़ की खपत में तेजी से वृद्धि हुई है। अब गुड़ निर्माता भी कृषि-उद्योग के रूप में मान्यता की मांग कर रहे हैं। सरकार के इस कदम ने कर्नाटक के गुड़ निर्माताओं के बीच आशा को फिर से जगाया है, विशेषकर मांड्या में जहां ऐसी इकाइयों की संख्या सबसे अधिक है। गुड़ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ मांड्या के अध्यक्ष सोमशंकर गौड़ा ने कहा कि इस फैसले से बंद होने के कगार पर खड़े गुड़ सेक्टर को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।

एफआरपी के ऊपर किसानों को मिलेगा 150 रुपया

गन्ना खरीद मूल्य में बढ़ोत्तरी की गई है। राज्य सरकार के इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया है। कर्नाटक गन्ना उत्पादक संघ के अध्यक्ष कुरबुर शांता कुमार ने कहा कि सरकार का आदेश उन किसानों के लिए एक तरह की जीत है जो पिछले 39 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। शांताकुमार ने कहा कि सरकार के आदेश के मुताबिक चीनी मिलों को एफआरपी मूल्य पर प्रति टन 100 रुपये और जो मिलें एथेनॉल का उत्पादन करते हैं उन्हें 150 रुपये अतिरिक्त देना होगा। 2022-23 में 7 करोड़ टन से अधिक गन्ने की आपूर्ति के लिए 950 करोड़ रुपये अतिरिक्त किसानों को मिलेंगे।

REAPING HAPPINESS BY THE TON.

DCM Shriram Ltd's sugar business is improving sugarcane productivity as well as the happiness index of farmers.

By working closely with farmers and equipping them with new soil management, soil improvement, efficient water usage and planting techniques, we have increased the sugarcane yield per hectare. Today, the results are there for everyone to taste. This rise in productivity is not only spreading smiles among farmers but is also ushering rural prosperity.



DCM Shriram e-Suvidha App is another feather in our cap, empowering farmers by providing them access to relevant information anytime, anywhere.



www.dcmshriram.com/sugar

Locations: Ajbapur | Rupapur | Hariawan | Loni (U.P.)

सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए हैं प्रतिबद्ध



जे.पी.दलाल

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी.दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने व गन्ना उत्पादक किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, जो चीनी मिलों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करेगी। दलाल ने यह जानकारी 4 जनवरी को गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए गठित कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता के दौरान दी। जिन अधिकारियों को कमेटी का सदस्य बनाया गया है उन्हें निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि सहकारी शुगर मिलों में चीनी की रिकवरी को 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया जाए ताकि मिलों के घाटे को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि पिछले साल चीनी का रिकवरी रेट कम रहा था। जिसके कारण शुगर मिलों का घाटा बढ़ गया। चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए अन्य विकल्पों की तलाश की जाए।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाते हुए सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दिशा में सहकारी चीनी मिलों में एथनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं। सहकारी चीनी मिलों के विकास में गन्ना उत्पादक किसानों का हमेशा अहम योगदान रहा है। किसानों को नवीनतम तकनीक अपनाकर गन्ना उत्पादन करना चाहिए। बैठक में कमेटी सदस्यों ने गन्ना किसानों व मिलों की स्थिति, चीनी के भाव और अन्य विषयों पर भी चर्चा की।

सरकार नहीं बढ़ाएगी गन्ने के दाम

हरियाणा सरकार इस साल प्रदेश में गन्ने के दाम नहीं बढ़ाएगी। सरकार ने पुराने दामों के आधार पर ही अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा में इस समय कई जगह किसान गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसान संगठन लगातार गन्ने के दाम बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले साल प्रदेश में गन्ने के दाम 362 रुपये प्रति क्विंटल तय किए थे। पड़ोसी राज्य पंजाब की सरकार ने इस बार गन्ने का एमएसपी 380 रुपये घोषित किया है। पंजाब की घोषणा के बाद से ही हरियाणा के किसान आंदोलन की राह पर हैं। प्रदेश में गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद सरकार ने गन्ने के दाम को लेकर अपनी स्थिति साफ नहीं की थी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद सरकार ने देर रात 362 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीद की अधिसूचना जारी कर दी है। इस सीजन में सरकार पुराने दामों पर ही गन्ने की खरीद करेगी।



उत्तराखण्ड

चार फीसदी बढ़ा गन्ने का क्षेत्रफल



हंसा दत्त पांडे

गन्ने का मूल्य बढ़ने व समय से भुगतान होने से किसानों का रुझान गन्ना उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष प्रदेश में चार फीसदी से अधिक गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ गया है। नए सत्र से नई प्रजाति के गन्ने की बुआई में इजाफा होने की संभावना भी जताई जा रही है। करीब दो-तीन वर्षों से किसानों को गन्ने का भुगतान समय पर किया जा रहा है। साथ ही गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ गया है। साथ ही गन्ने की नई प्रजातियां भी विकसित की जा रही है। जिसके चलते गन्ने की फसल बोन के लिए किसानों का रुझान बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में गन्ने का उत्पादन होता है। अधिकारियों के मुताबिक ऊधमसिंह नगर और खटीमा में अन्य जनपदों की अपेक्षा गन्ने का रकबा अधिक बढ़ा है।

सत्र 2022-23 में ऊधमसिंह नगर में 13436.284, नैनीताल में 1025.603, हरिद्वार में 29928.833, देहरादून में 1885.233 कुल 46275.953 यानी 99.90 प्रतिशत रकबे में शीघ्र प्रजाति के पौध गन्ने की बुआई की गई। सामान्य प्रजाति का पौधा ऊधमसिंह नगर में 161.572, नैनीताल में 39.668, हरिद्वार में 19.784, देहरादून में 151.121 कुल 372.145 यानी 0.81 प्रतिशत रकबे में बुआई की गई।

इसके अलावा यूएस नगर में 11175.200, नैनीताल में 1077.319, हरिद्वार में 30646.809, देहरादून में 2537.526 कुल 45436.854 हेक्टेयर क्षेत्र में शीघ्र व सामान्य गन्ना पेड़ी की फसल बोई गई। चारों जिलों में कुल 91712.807 रकबे में शीघ्र व सामान्य गन्ने की बुआई की गई। सत्र 2021-22 में 88022.072 रकबे में गन्ना बोया गया था। जिसके सापेक्ष इस सत्र में 3690.735 हेक्टेयर यानी 4.19 फीसदी अधिक क्षेत्रफल में गन्ने का उत्पादन हुआ है।



गन्ना एवं चीनी आयुक्त हंसा दत्त पांडे के मुताबिक गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ गया है। किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान भी समय से हो रहा है।

गन्ने की नई उन्नत प्रजातियां भी विकसित की जा रही हैं। इससे किसानों का रुझान गन्ने की खेती की ओर बढ़ रहा है। गन्ने की फसल में लागत कम आती है। एक बार फसल बोन पर दो-तीन बार काटी जा सकती है। ऊधमसिंह नगर और खटीमा में सबसे अधिक गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है। पूरे प्रदेश में करीब 5 प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ा है।

गन्ना किसानों तक नहीं पहुंच रहा एथेनॉल योजना का लाभ

महाराष्ट्र में लगभग 200 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 76 मिलों में एथेनॉल प्लांट लगा हुआ है। राज्य के गन्ना किसानों का कहना है कि गन्ने से एथेनॉल के बढ़ते उत्पादन के बावजूद उनकी आय में ज्यादा अंतर नहीं आया है। महाराष्ट्र के चीनी मिलों में एथेनॉल अथवा अल्कोहल का उत्पादन कोई नई बात नहीं है। पहले अल्कोहल का इस्तेमाल मिल देसी शराब बनाने में करते थे। बहुत से मिलों की अपनी खुद की स्थानीय ब्रांड की देसी शराब है। लेकिन पिछले तीन सालों से बहुत से मिलों में अब एथेनॉल का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में बढ़ा है। अब बहुत सी मिलें अपने एथेनॉल को एथेनॉल मिश्रण योजना (ईबीपी) के लिए भेज रहे हैं। कराड कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक भरत खांडेकर ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया कि एथेनॉल बायोमास पर आधारित ऊर्जा का एक स्रोत है और नवीकरणीय ऊर्जा है। इसे जब पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो एक अच्छा ईंधन साबित होता है।

गन्ना किसानों का कहना है कि गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) एक अच्छी व्यवस्था है जो न्यूनतम निर्धारित मूल्य किसानों को दिलाती है। लेकिन बढ़ती महंगाई और कारखानों के बढ़ते लाभ के मद्देनजर किसानों को अपने गन्ने के लिए अच्छा दाम मिलना चाहिए। किसानों को कहना है कि एथेनॉल के कारण कारखानों के बढ़ते लाभ के बावजूद किसानों को इस पूरे परियोजना से ज्यादा फायदा नहीं मिला है। विश्वास जादव कराड में रहने वाले 40 वर्षीय किसान हैं जो बलीरजा शेतकारी संगठन में एक सक्रिय सदस्य हैं। जादव ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया महाराष्ट्र में बहुत से चीनी मिलों में गन्ने से एथेनॉल और अवशेष से बिजली बनाई जा रही है। लेकिन गन्ना उगाने वाले किसानों की बात करें तो उनकी आय में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। हमें गन्ने के उत्पाद से केवल एफआरपी मिलता आ रहा है जो बढ़ते महंगाई के अनुपात में नहीं है।

कराड के बहुत से किसानों ने बताया कि गन्ने से होने वाले आय में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया है। महाराष्ट्र के गन्ना के किसानों को जहां एफआरपी की दर से गन्ने के उत्पाद

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले तीन सालों में गन्ने के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में इस राज्य में 10,14,94,920 टन गन्ने का उत्पादन हुआ। भारतीय चीनी मिल संगठन (आईएसएमए) के आंकड़े कहते हैं कि 2021-22 में भारत से कुल चीनी निर्यात में महाराष्ट्र का योगदान 61 प्रतिशत था।

का भुगतान किया जाता है वही दूसरे कुछ प्रदेशों में जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और तमिलनाडु में गन्ने के किसानों को राज्य सलाहकार मूल्य (एसएपी) दिया जाता है। गन्ने के लिए एफआरपी केंद्र सरकार तय करती है। 2022-23 के चीनी वर्ष (अक्तूबर से सितम्बर) के लिए केंद्र सरकार ने एफआरपी की दर 305 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। वही उत्तर प्रदेश में जहां एसएपी के दरों से गन्ने के किसानों का भुगतान किया जाता है, राज्य सरकार ने 340 रुपये प्रति क्विंटल दर तय किया है।

अक्सर यह देखा गया है कि राज्यों में मिलने वाले एसएपी की दरें एफआरपी दरों से अक्सर 10-15 प्रतिशत अधिक होती हैं। महाराष्ट्र के शक्कर आयुक्त शेखर गायकवाड का मानना है कि एथेनॉल मिश्रण की योजना से किसानों को आने वाले दिनों में मुनाफा राजस्व साझेदारी फॉर्मूला (आरएसपी) के अंतर्गत कारखाने दे सकते हैं। इस फॉर्मूले के अंतर्गत कारखानों को अधिक फायदा होने पर उन्हें यह राजस्व किसानों में बांटना होगा।

एथेनॉल के मद्देनजर चीनी कारखानों की बदलती भूमिका

भारत सरकार ने 2013 में एथेनॉल मिश्रण की योजना बनाई थी लेकिन यह बड़े पैमाने पर कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। 2019 में केंद्र सरकार ने नवम्बर 2022 तक पूरे देश में पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा था। यह लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया गया। 2018 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति

भी प्रकाशित की जिसमें एथेनॉल बनाने के लिए दूसरे अन्य साधन जैसे गन्ने का रस, मक्का, टूटी हुई चावल, गेहूं आदि के प्रयोग को भी इजाजत दी गई। भारत में एथेनॉल का मुख्य स्रोत गन्ना है। अब भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रण का नया लक्ष्य भी रखा है।

महाराष्ट्र में अभी लगभग 200 चीनी मिल हैं जिसमें से 76 मिलों के पास एथेनॉल प्लांट हैं। जबकि 46 ऐसे स्वतंत्र एथेनॉल अथवा अल्कोहल बनाने के डिस्टिलरी भी हैं जो चीनी मिलों से शीरा लेकर अपने प्लांट में एथेनॉल बनाते हैं। लेकिन एथेनॉल के बढ़ते मांग के मद्देनजर चीनी मिलों के ढांचे में बदलाव धीरे धीरे आता दिख रहा है। शक्कर आयुक्त गायकवाड ने बताया कि अभी यह चीनी के कारखाने गन्ने का 80 प्रतिशत प्रयोग चीनी बनाने में करते हैं जबकि 20 प्रतिशत भाग एथेनॉल के उत्पादन में जाता है। विश्व में ब्राजील जैसे देश है जहां ज़्यादातर गन्ने का प्रयोग एथेनॉल बनाने में प्रयोग होता है। धीरे धीरे महाराष्ट्र के चीनी के कारखानों में भी यह संरचना बदल सकता है।

उन्होंने बताया कि अभी जितने भी चीनी के कारखाने हैं जिनके पास इथेनॉल बनाने के प्लांट नहीं हैं उन सभी ने केंद्र सरकार से इसके लिए आवेदन किया है। अब आने वाले दिनों में गन्ने से एथेनॉल बनाने का अनुपात बदलने वाले हैं। आने वाले दिनों में कारखाने यह तय करेंगे की गन्ने का कितना प्रतिशत भाग एथेनॉल बनाने में लगाना चाहते हैं। मेरे अनुमान से अगले कुछ वर्षों तक प्रति वर्ष 5-

6 प्रतिशत अधिक गन्ने का प्रयोग एथेनॉल के उत्पादन में हो सकता है। महाराष्ट्र इस एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसके पास 247.2 करोड़ लीटर प्रति वर्ष तक की क्षमता है। गायकवाड़ के अनुसार 2021-22 में महाराष्ट्र में 118 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया गया जबकि अगले साल तक यह 140 करोड़ लीटर तक पहुँच सकता है। महाराष्ट्र अभी 30 प्रतिशत एथेनॉल की मांग को पूरा करता है।

चुनौतियाँ और समाधान

गन्ना महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 26 जिलों में पैदा होता है। एक अध्ययन के अनुसार गन्ने की खेती राज्य में केवल 6 प्रतिशत भाग में होती है लेकिन इसमें सिंचाई का 70 प्रतिशत पानी लग जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एथेनॉल की अधिक मांग के कारण गन्ने की खेती का विस्तार लाज़मी है। इस वजह से वातावरण और दूसरी फसलों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। (मनीष कुमार)

गन्ना बकाया के लिए उच्च न्यायालय में हुआ केस

चेन्नई स्थित अरुण शुगर लिमिटेड को गन्ने की आपूर्ति कौं देय 110 करोड़ बकाया राशि जारी करने के लिए एक किसान ने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलिंगिंग एग्रीकल्चरिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अय्याकन्नू ने यह भी मांग की है कि अदालत राज्य सरकार को किसानों के नाम पर कंपनी द्वारा 'धोखाधड़ी' से प्राप्त किए गए ऋणों का निर्वहन करने का निर्देश दे। याचिकाकर्ता अय्याकन्नू के अनुसार चीनी मिल कुड्डलोर के ए-सिथुर गांव में स्थित है। मिल की स्थापना के बाद से ही गांव के किसानों को मिल को गन्ना आपूर्ति करने को निर्धारित किया गया था। किसान नियमित रूप से गन्ने की आपूर्ति कर रहे थे, लेकिन मिल ने 2013 से 2018 तक कई भुगतानों में चूक की।

चीनी मिल बनायेगी प्रेस मड से सीएनजी

नेचुरल शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज चीनी मिल उस्मानाबाद के कलंब तालुका में स्थित है। मिल बायो सीएनजी बनाने के लिए प्रेस मड का उपयोग करने जा रही है। अब मिल वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन करने जा रही है। मिल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बी. बी. ठोंबरे ने कहा कि इस तकनीक से मिलों को कृषि अपशिष्ट का पुनः उपयोग करने में मदद मिलेगी, जिसका अब तक केवल खाद के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। प्रेस मड गन्ने के रस को बार-बार छानने पर प्राप्त होता है। फिल्टर समय-समय पर साफ किए जाते हैं, और वेस्ट को मिल के यार्ड में जमा किया जाता है। गन्ने की पेराई करने पर लगभग 3 से 4 प्रतिशत प्रेस मड प्राप्त होता है। मिलें इस प्रेस मड को खाद के रूप में पुनर्चक्रित करके क्षेत्र के किसानों को आपूर्ति करती हैं।



द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ठोंबरे ने बताया कि इस प्रक्रिया में प्रेस मड के BOD (biological oxygen demand) और COD (chemical oxygen demand) को कम करना और प्राकृतिक गैस को घोल से अलग करना शामिल होगा। जबकि प्राप्त गैस को संपीड़ित किया जाएगा और ईंधन कंपनी को जैव सीएनजी के रूप में बेचा जाएगा। इस तकनीक का एक पायलट प्लांट कोल्हापुर स्थित वारणा सहकारी चीनी मिल में संचालित किया गया है। उस्मानाबाद में संयंत्र प्रति दिन 100 टन प्रेस मड का उपयोग करेगा और 5-6 टन बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मिल से 75 रुपये किलो की दर से इसे खरीदने के लिए तैयार हो गई है।

छुड़ाये गये बंधक रखे गए 19 मजदूर

एमपी के सरगुजा जिले से 19 मजदूरों का सौदा एक व्यक्ति द्वारा महाराष्ट्र के बीड़ जिले में कर दिया गया था। इस मामले में मजदूरों के परिजनों ने प्रशासन से उन्हें मुक्त कराने की गुहार लगाई गई थी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने एक टीम गठित कर महाराष्ट्र भेजा। टीम द्वारा वहां बंधक बनाकर रखे गए जिले के 19 श्रमिकों को मुक्त कराया गया। 29 दिसम्बर को उन्हें अंबिकापुर लाया गया। घर वापसी कराने पर उन्होंने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। सरगुजा के सीतापुर थाना ग्राम पंचायत नकना के 13 मजदूर और लुंड्रा थाना बरगीडीह के 6 मजदूरों को काम दिलाने के बहाने महाराष्ट्र में बंधक बनाया गया था। गन्ना काटने और ज्यादा मजदूरी राशि दिलाने का लालच देकर 19 श्रमिकों को महाराष्ट्र ले जाने के पीछे सरगुजा के ही लुंड्रा थाना क्षेत्र के बरगीडीह निवासी पुष्पनंद गिरी का नाम सामने आया था।

वह सरगुजा क्षेत्र के भोले-भाले युवकों को मजदूरी दिलाने के नाम पर महाराष्ट्र के बीड़ ले गया, फिर यहां उनका सौदा कर राशि लेकर फरार हो गया। इससे 19 मजदूर डर के साए में पिछले एक महीने से कार्य करने को विवश थे। परिजनों ने बताया था कि महाराष्ट्र में ठेकेदार द्वारा उनकी मोबाइल छीन ली गई है तथा 6 श्रमिकों के साथ मारपीट भी की गई है। कलेक्टर कुंदन कुमार को श्रमिकों के परिजनों के माध्यम से सूचना मिली कि महाराष्ट्र के बीड़ जिले में 19 श्रमिकों को बंधक बनाकर रखा गया है जिस पर कलेक्टर ने त्वरित कार्यवाही करते श्रमिकों की रेस्क्यू के लिए नायब तहसीलदार कोमल साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर महाराष्ट्र भेजा।

महाराष्ट्र में ये श्रमिक विभिन्न संस्थानों में श्रमिक का कार्य कर रहे थे। अंबिकापुर की टीम 26 दिसंबर को रवाना होकर 27 दिसंबर को बीड़ महाराष्ट्र पहुंची। टीम ने महाराष्ट्र के बीड़ जिले के जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर दबिश दी। इसके पश्चात श्रमिकों को बंधनमुक्त कराया गया। उपरोक्त सभी श्रमिकों को अवमुक्त कराकर 29 दिसंबर को सकुशल अंबिकापुर लाया गया।





TAYALTECH CONSULTANTS

I.M.F.L. DISTILLERIES & BREWERIES



TAYALTECH CONSULTANTS is a professionally managed group engaged in the consultancy business for setting up I.M.F.L. Distilleries & Breweries Plants at NATIONAL & INTERNATIONAL LEVEL. Promoted by eminent consultant **Mr. R.C.Tayal** from INDIA. Who has got over 30 years of rich experience in Technology Transfer Successfully at National and Global level with respect of Marketing. Blending, Alcohol Technology and fermentation.



Specialization

- ✍ Blending of I.M.F.L. Products.
- ✍ Development / Concept / Designing of new products.
- ✍ Erection & Commissioning of RS, ENA, GRAIN SPIRIT & BREWERY PLANT.
- ✍ Designing Erection + Commission of Effluent Treatment Plant.
- ✍ Improvement in Efficiency of RS , ENA, GRAIN, MALT SPIRIT & BREWERY PLANT
- ✍ Cost Control / Productivity improvements in Plant Operation Packaging.
- ✍ Fuel Ethanol Plant.
- ✍ RTD Alcoholic Beverages.

Overseas
Project Handling at
Kenya, Nigeria,
Angola, Congo
Sudan, Malaysia
Ghana etc.

IMPORTER &
EXPORTER OF
PACKING MATERIALS,
PLANT &
MACHINERIES

TTC House

IMPORT EXPORT
CODE NO. - 0507002539

A-5/B 141, PASCHIM VIHAR, NEW DELHI - 110063 INDIA • TEL : +91-11-25253835
MOBILE : 9654293454, 9810208820 • E-Mail : rctayal2004@yahoo.co.in, blendwellsco@gmail.com

हैप्पी सीडर पर मिलेगी 80 प्रतिशत सब्सिडी

किसानों की आय बढ़ाने एवं कृषि की लागत को कम करने के लिए सरकार कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, सभी किसान इन कृषि यंत्रों को खरीद सकें इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जाता है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत इस वर्ष बिहार सरकार 9405.54 लाख रुपए की लागत से किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने जा रही है। योजना के तहत कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा, जिसमें हैप्पी सीडर कृषि यंत्र शामिल है।

बिहार सरकार 'कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना वर्ष (2022-23)' में कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है, जिसमें खेत की जुताई, बुआई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी इत्यादि तथा गन्ना एवं उद्यान से सम्बंधित कृषि यंत्र शामिल है। बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन में शामिल कृषि यंत्रों की खरीद पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है, इसमें हैप्पी सीडर को भी शामिल किया गया है। यह कृषि यंत्र कम्बाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद बचे हुए फसल अवशेष (पुआल) को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में फैला देता है साथ ही गेहूँ की बुआई भी कृतार में कर देता है। इस कृषि यंत्र को 45-50 पीटीओ एचपी के ट्रैक्टर में लगाकर संचालित किया जाता है।

बिहार सरकार राज्य के किसानों को हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 प्रतिशत अधिकतम 1,10,000 रुपए एवं अत्यंत पिछड़ा/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 80 प्रतिशत अधिकतम 1,20,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।



श्रीजी शुगर मिल ने बढ़ाए गन्ना के दाम



बैतूल के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। यहां किसानों को श्रीजी शुगर मिल सोहागपुर ने नए साल पर बड़ी सौगात दी है। मिल प्रबंधन ने किसानों से खरीदे जाने वाले गन्ने के दामों में खासी बढ़ोतरी कर दी है। श्रीजी शुगर मिल के संचालक अभिषेक गोयल ने बताया कि मिल प्रारंभ करने के दौरान किसानों से गन्ना की खरीदी मिल गेट पर 305 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही थी। अब 10 जनवरी से गन्ना खरीदी के दाम 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिए जाएंगे। दाम में इजाफा किए जाने से किसानों को खासा लाभ मिल सकेगा। दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला यहीं नहीं थमेगा, बल्कि इसके बाद भी दाम में इजाफा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके बाद 1 फरवरी से किसानों को प्रति क्विंटल गन्ने के दाम 325 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त होंगे। उसके पश्चात 21 फरवरी से गन्ना की खरीदी 335 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। श्री गोयल ने सभी किसानों से अपील की है कि गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए गन्ने के दाम समय-समय पर बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसे देखते हुए किसान धैर्यपूर्वक अनुमति लेकर ही गन्ना की कटाई करें। मिल प्रबंधन के द्वारा सभी किसानों का गन्ना खरीदा जाएगा। इस कारण से औने-पौने दामों पर गन्ना अन्य लोगों को न बचें।



«**मेघालय**» कमाई के मामले में मेघालय के किसान हैं नंबर वन

हर साल आने वाली आपदा बाढ़, बारिश और सूखा किसानों को पनपने नहीं देती है। किसान खेत में लाखों रुपये के बीज और अन्य लागत लगाकर बुआई करते हैं। फसल को नुकसान होने पर किसान केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट से मदद की गुहार लगाते हैं। सरकारें किसानों की मदद भी करती हैं। अब केंद्र सरकार के प्रति कृषि परिवार मासिक औसत आय के आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों को देखें तो कुछ राज्यों में किसान परिवारों की मासिक आय में सुधार हुआ है। वहीं कुछ की हालत आर्थिक तौर पर खराब हैं।

केंद्र सरकार की ओर से जो आंकड़े सामने आए हैं। उनमें कुछ राज्यों की मासिक आय ही 20 हजार रुपये प्रति महीने के पार हैं। कई राज्यों में तो किसान परिवार 12 से 13 हजार रुपये महीना में ही खर्चा पानी चला रहे हैं। इस मामले में मेघालय नंबर वन बना है। आंकड़ों के अनुसार प्रति कृषक परिवार का औसत मासिक आय मेघालय में 29,348 रुपये है। पंजाब की 26,701 रुपये,

हरियाणा 22,841 रुपये, अरुणाचल प्रदेश 19,225 रुपये, जम्मू और कश्मीर 18,918 रुपये, केंद्र शासित प्रदेशों का समूह की आय 18,511 रुपये, मिजोरम 17,964 रुपये, केरल 17,915 रुपये, पूर्वोत्तर राज्यों का समूह 16,863 रुपये, उत्तराखंड 13,552 रुपये, कर्नाटक 13,441 रुपये, गुजरात 12,631 रुपये, राजस्थान 12,520 रुपये, सिक्किम 12,447 रुपये और हिमाचल प्रदेश में मासिक इनकम 12,153 रुपये है।

केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों को इनकम बढ़ानी है तो पारंपरिक खेती के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन पर भी हाथ आजमाने होंगे। बागवानी फसलों का उत्पादन कर भी किसान अच्छी पैदावार पा सकते हैं। पंजाब में बागवानी फसलों पर जोर रहता है। इसके अलावा अन्य फसलें पैदा की जाती हैं। यही हाल मेघालय का है। इसी कारण देश के किसान अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। पंजाब में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, गन्ना, तिलहन और कपास शामिल हैं।

UPCOMING EVENTS TIMELINE

Date	Events	Location
7-8 Jan 2023	Sugar & Ethanol India Conference 2023	Hotel Pulman New Delhi
20-23 Feb 2023	ISSCT Congress 2023	HICC Hyderabad

U.P. CO-OPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD.

9-A, Pratap Marg Lucknow Tel. (0522) 2200183
(0522) 2628310, Fax: (0522) 2627994

levy molasses Online eTender Notice

The e-Bids EMD is Rs. 20 per quintals Online e-Bids are invited for the sale of levy molasses 250000 quintals molasses from Cooperative Sugar Mills of U.P to bonafide Consumers to whom license have been issued by the Excise Commissioner & Molasses Controller, Allahabad, U.P. **E-Tender can be uploaded up to 6.30 P.M on dt. 27-1-2023 and Technical & Financial Bid will be opened on 28-1-2023 at 11 -30 AM, 3.00 PM** respectively. The details for submission of e-Bids will be available on the e- Bids portal and also on Federation website from 19/01/2023 at 6.00 P.M. The Federation reserves the right to cancel any or all the e-Tender without assigning any reason. The decision of the Managing Director shall be the final and binding.

इस निविदा के सम्बन्ध में सभी संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, समय बृद्धि आदि को केवल <http://eTender.up.nic.in> एवं www.upsugarded.org पर ही दिया जायेगा। निविदादाता अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से इन वेबसाइट्स को पढ़ते रहें।

Date - 20.01.2023

MANAGING DIRECTOR

U.P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.

VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010
Ph. No. 0522-2307826/28 www.upsugcorp.in
Email : upstatesugarcorporation@gmail.com

Date: 24.01.2023

EXPRESSION OF INTEREST

For Establishment of Sugar Mill and/or Distillery Plant Under EPC Mode and Operation & Maintenance of Sugar Mill, Co-Generation Plants

U.P. State Sugar Corporation Ltd. is engaged in the business of manufacture of Sugar and its By-products viz Bagasse, Molasses and Pressmud. At present, three units of Corporation are in Operation viz Mohiuddinpur (Meerut) of 3500 TCD capacity sugar mill & 15 MW cogen plant, Pipraich (Gorakhpur) and Munderwa (Basti) both of 5000 TCD capacity Sugar Mill & 27 MW cogeneration. Expressions of Interest (EOI) are invited from the Companies/ Manufacturers etc engaged in establishment of Sugar Mills, Distilleries for establishing Sugar Mill and/or Distillery in units of UPSSCL.

Apart from this EOI are also invited from the Companies/Agencies etc for Operation & maintenance of Sugar Mills, Refinery Plant, Co-generation Plants and Distillery etc. for the plants established or to be established in units of UPSSCL.

The interested Parties may visit to website www.upsugarcorp.in to download the scope, pre-qualification criteria, draft bidding terms and conditions. A meeting in this regard will be held with the interested parties on **31.01.2023 at 3:00 PM** in the meeting hall of New Scholar Hostel of Office of Commissioner, Cane & Sugar, UP situated at 17, New Berry Road, Dali Bagh, Lucknow-226001.

MANAGING DIRECTOR

गन्ना किसानों व चीनी उद्योग पर प्रथम हिन्दी मासिक पत्रिका

शुगर टाइम्स

कार्यालय

485, ममफोर्डगंज, प्रयागराज-211002 (उ.प्र.)

फोन/फैक्स : 0532-2440267 मो. : 73554 53462, 94153 05911

www.sugartimes.co.in, Email-upsugartimes@gmail.com

शुगर टाइम्स पत्रिका की सदस्यता तथा इसमें विज्ञापन हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान कृपया नगद न करके चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में ही करें। अपरिहार्य कारणों में नगद भुगतान के समय पत्रिका में दिये गये मोबाईल नम्बरों पर सम्पर्क करके ही नगद भुगतान करें। अन्यथा आपकी सदस्यता शुल्क या अन्य प्रकार के भुगतान हेतु शुगर टाइम्स की जिम्मेदारी नहीं होगी-सम्पादक

सदस्यता शुल्क

निशान लगायें	अवधि	कूरियर/रजि.डाक	ई- मैगजीन
<input type="checkbox"/>	1 वर्ष	2000/-	1000/-
<input type="checkbox"/>	2 वर्ष	3600/-	1600/-
<input type="checkbox"/>	3 वर्ष	5000/-	2000/-
<input type="checkbox"/>	आजीवन	15,000/-	8,000/-

Our Banker Name

**Uco Bank, Branch Mumfordganj, Prayagraj.
Current A/C No. - 16110210000861
IFSC Code - UCBA0001611**

नाम- जन्मतिथि-

पद- कम्पनी-

पता- पिन-

ई मेल- फोन-

चैक/डीडी/मनीट्रांसफर संख्या-

उपलब्ध कोरियर सेवा का नाम-

दिनांक-

हस्ताक्षर-



AVANT-GARDE

ISO 9001-2015 CERTIFIED ORGANIZATION



TURNKEY SOLUTIONS FOR DISTILLERY PROCESS AND SLOP INCINERATION COGEN PROJECTS

Distillery Plant in existing or new Sugar Plants or Stand alone plants using Sugar Syrup / Raw Sugar / B Molasses / C Molasses or / and Grains - Rice, Maize, Millets, etc.,

- ★ Feasibility Report / DPR
- ★ Basic Engineering
- ★ Detailed Engineering
- ★ Process Engineering
- ★ Procurement Assistance
- ★ Project Management
- ★ Inspection & Expediting Services
- ★ Supervision of Erection & Commissioning
- ★ Plant Automation Engineering

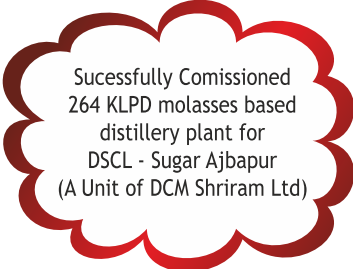


Multi-Feed & Multi Product Distillery



360 KLPD Grain Based Distillery For BCML

Design & Detailed Engineering of SLOP Incineration Boilers



Successfully Commissioned 264 KLPD molasses based distillery plant for DSCL - Sugar Ajbapur (A Unit of DCM Shriram Ltd)

ZERO LIQUID DISCHARGE

Commissioned **20** Distilleries of **2500** KLPD
Under Execution **30+** Distilleries of **5000** KLPD



Years of engineering experience



KLPD of Distillery Projects



MW Power Projects



Professionals



Clients



Countries

Process Engineering | Civil & Structural | Mechanical | Electrical & Instrumentation Quality Control | Project Management | Site Services

AVANT-GARDE ENGINEERS AND CONSULTANTS (P) LTD.,
68A, Kundrathur High Road, Porur,
Chennai - 600 116, Tamil Nadu, India.
Tel: +91-44-4598 1200, +91-44-2482 7843
Fax: +91-44-2482 8531
Email: agsc@avant-garde.co.in
Web : www.avantgarde-india.com



AVANT-GARDE SYSTEMS AND CONTROLS (P) LTD.,
67A, Kundrathur High Road, Porur,
Chennai-600 116, Tamil Nadu, India.
Tel: +91-44-4598 1200, +91-44-2482 7843
Fax: +91-44-2482 8531
Email: agsc@avant-garde.co.in
Web : www.avantgarde-india.com



AVANT-GARDE ENGINEERS AND CONSULTANTS (FZC),
Executive Suite, P.O. Box: 122632,
Sharjah,
U.A.E.
Tel: + 971566924002
Email: info@avant-gardefzc.com
Web : www.avant-gardefzc.com



follow us: "Avant Garde India"



CAN ENGINEERING
SOLUTIONS PVT. LTD.

EPC Solutions for Grain Based Distilleries

Turnkey Rice Mill Solutions
Post Harvest Grain Machinery
Material Handling Solutions
Easily Available Spare Parts
Quality Assurance
24x7 Customer Support

R.N.L- UPHIN/2018/75505
Postal Reg No. L-2/Reg/AD/322/2022-24



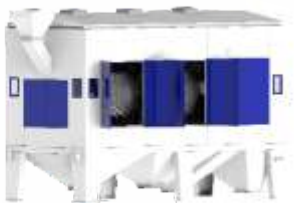
PRE CLEANER



STONE SEPARATOR



VIBRO CLASSIFIER



*ROTATRY DRUM
CLEANER*



BUCKET ELEVATOR



GRAIN HAMMER MILL



CHAIN CONVEYOR

Sona Machinery Pvt. Ltd.

 Factory Unit 1: F16, Sector A3, Tronica City Industrial Area, Loni, Ghaziabad, U.P. India-201102

 +91-9599002201

 inquiry@sonamachinery.com

 www.sonamachinery.com